

सं. ३६ (अंक ५६९), अक्टूबर-नवम्बर १९७३

पृष्ठ ३००

सामयिक वार्ता



समाजवादी जन परिषद का १३ वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन
और
पारित राजनीतिक-आर्थिक प्रस्ताव

कविता



हैंसो हैंसो जल्दी हैंसो

रघुवीर सहाय

हैंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है-
हैंसो अपने पर न हैंसना क्योंकि उसको कड़वाहट
पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे
ऐसे हैंसो कि बहुत खुरा न मालूम हो
बरना शक होगा कि यह शाख्स शर्म में शामिल नहीं
और मारे जाओगे

हैंसते-हैंसते किसी को जानने मत दो किस पर हैंसते हो
सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्ता होकर
एक अपनापे की हैंसी हैंसते हो
जैसे सब हैंसते हैं बोलने के बजाय
नितनी बेर उँचा गोल गुंबद गुंजता रहे, उतनी बेर
तुम बोल सकते हो अपने से
गुंज धमते-धमते फिर हैंसना
क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जूम में फँसे
अंत में हैंसे तो तुम पर सब हैंसेंगे और तुम बच जाओगे

हैंसो पर चुटकुलों से बचो
उनमें शब्द हैं
कहीं अनमैं अर्थ न हों जो किसी ने सौ साल पहले दिए हों

बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हैंसो
ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे
और ऐसे मौकों पर हैंसो
जो कि अनिवार्य हों
जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार
जहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता
उस गरीब के सिवाय
और वह भी अक्सर हैंसता है

हैंसो-हैंसो जल्दी हैंसो
इसके पहले कि वह चले जाएं
उनसे हाथ मिलाते हुए
नज़रें नीची किए
उसको पाद धिलाते हुए हैंसो
कि तुम कल भी हैंसे थे

‘रघुवीर सहाय संचयिता’ (संपादक : कृष्ण कुमार) से साभार

सामयिक वार्ता

जनवरी-फरवरी 2023 वर्ष 45 अंक 9-10

संस्थापक संपादक : किरान पटनायक

संपादक : अफलाहून

संपादक सहायक

श्री. बलधोर जैन, अरविंद मोहन, हरिमोहन, राजेंद्र राजन, प्रियदर्शन,
आरुण त्रिपाठी, श्री. मंदेश विक्रम, लोकार्क द्विवेदी, संजय गौतम,
चंचल मुखर्जी, कमल बनर्जी, संजय प्रारती

परामर्श मंडल

सचिदानंद सिन्हा, श्री. फरमौर उम्ल, स्मिता
रूप सन्ना : सुशील कान्ति
आचरण : अभिजीत सेनागुप्त (राना)

कार्यालय : 20 ए स्मरपुर जगौर, पंडित नगर
दिल्ली - 110091

ईमेल : varta3@gmail.com
sjp.dellhistate@gmail.com

सदस्यता शुल्क :

एक प्रति : 20 रुपए
वार्षिक शुल्क : 200 रुपए
संस्थागत वार्षिक शुल्क : 300 रुपए
छह साला शुल्क : 1000 रुपए
आजीवन शुल्क : 3000 रुपए

खाता नाम : सामयिक वार्ता या Somyik Varta

बैंक ऑफ बड़ोदा (Bank of Baroda)

शाखा : सोनारपुरा, वाराणसी (उ. प्र.)

Sonarapura, Varanasi (U.P.)

आईएफएससी कोड

खाता संख्या : 40170100005458

IFSC : BARB0SONARP

(क्या कुतरा B के बाद जोरो है, ओ नहीं है, एस के बाद O (ओ) है

MICR CODE : 221012030

(इस खाते में पैसे जमा करने तथा ग्राहक के पते की सूचना ईमेल

अथवा मॉबाइल 8765811730 / 8004085923 पर दें।)

इस अंक में

हैंसो हैंसो जहन्नों हैंसो

रघुवीर सहाय / 2

संपादकीय / 4

नजरिया / 5

सामयिक वार्ता की यात्रा

आतुल कुमार / 6

अब 2024 के आम चुनाव की चुनौती

महेश विक्रम / 8

नफरत की राजनीति और स्त्री प्रश्न

निशा शिवरकर / 11

आदिवासियों का संकट

रंजीत कुमार महली / 13

समाजवादी जन परिषद का 13 वां राष्ट्रीय सम्मेलन

अभिमान्यु / 15

संजय के राष्ट्रीय सम्मेलन से पारित

राजनैतिक आर्थिक प्रस्ताव / 18

आदिवासी, देशज, बाहर के कौन

किरान पटनायक / 25

गांधी पर प्रहार

अध्युतानंद किशोर नवीन / 27

वरिष्ठ समाजवादी नेता अकरम हुसैन नहीं रहे / 30

साथी अख्तर हुसैन नहीं रहे / 32

अभिव्यक्ति के माध्यमों के चरित्र और स्वरूप को बदलने की साजिश

विषयता, जाति, धर्म के आधार पर सिद्धांतहीन व वोट की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियाँ और उनको सरकारें अभिव्यक्ति के माध्यमों के चरित्र व स्वरूप को बदल देने पर आमादा हैं। उनके लिए यह जरूरी हो गया है क्योंकि ऐसा नहीं करने पर उनके अनकृत एक्स्पर्फा महसूस नहीं बन पाएगा और उनकी मंशाएँ पूरी नहीं हो पाएंगी। उनको मंशाओं में एक मंशा देश को वैश्वीकरण और बानारवाद में झोंक देना है। वैश्वीकरण और बाजारवाद के दबाव में ऐसा किया जा रहा है या हो रहा है।

अभिव्यक्ति और उसकी आजादी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष पाबंदी लगाने की कई बार कोशिश हो चुकी है। जब भी ऐसी कोशिश हुई और जहाँ कहीं हो हुई, इसका पुरजोर विरोध हुआ। वह साफ है कि इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ऐसा करने पर विरोध में देश उठ खड़ा होगा। अभिव्यक्ति और उसकी आजादी देश के लोकतंत्र और उसके अनुरूप व्यवस्था का एक मानदंड है। पाबंदी तानाशाही का द्योतक है।

आजादी के बाद खासकर 1972-73 से 1977 तक शासक पार्टी और उसकी केंद्र और राज्य की सरकारों ने अभिव्यक्ति की आजादी पर घोर प्रहार किया। उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। गतीमान बंध हुआ कि राजनीतिक पार्टियाँ और उनको सरकारें संचाल गईं। लेकिन 1990-91 के बाद सत्ता में रही पार्टियों के आत्मा नेताओं ने अभिव्यक्ति के माध्यमों यानी अखबारों-पत्रिकाओं के खिलाफ यह प्रहार शुरू किया कि ये झूठ लिखते और बदनाम करते हैं। अखबारों-पत्रिकाओं का मजाक उड़ाने का सिलसिला चल पड़ा। उनके इस कर्तूत से एक तरफ राजनीतिक व सरकारी हस्तियों को प्रेस जगत को दबोधाते रहने का बल मिला, दूसरी ओर अखबारों-पत्रिकाओं के खिलाफ चाहोल बना और उनके प्रति आम लोगों का विश्वास उभगाया।

अखबारों-पत्रिकाओं ने अपने चरित्र व स्वरूप की रक्षा के लिए जो रणनीति अपनाई, वह उनके लिए घातक हुई। उन्होंने अपने बचाव में बतौर बिकल्प ऐसा कुछ नहीं किया जिससे सरकारी या गैर सरकारी मदद (यानी विज्ञापन) के बगैर वे चल सकें। वे सरकारों,

राजनीतिक पार्टियों, धृनीपतियों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर रहने लगे, जो उन्हें वे विज्ञापन के लिए दंडवत करने लग गये। अखबारों-पत्रिकाओं में वही होने लगा, जो अभिव्यक्ति और उसकी आजादी के विरोधी चाहते रहे हैं।

अखबारों और पत्रिकारों में संपादकीय विभाग को औकात धीरे-धीरे कम कर दी गई, विज्ञापन और प्रसार के विभाग ही सब कुछ हो गए। प्रबंधन यानी मालिकों की टीम न्याया भूनाफा को व्यावसायिकता के मकसद से यहाँ काने लगी, जो सत्ता चाहती है।

एक समय था जब अखबारों-पत्रिकारों में खबरों को प्राथमिकता दी जाती थी। खबरों की छापने के लिए विज्ञापन हटा दिए जाते थे। अब खबरें बल्ले न छपें, विज्ञापन जरूर छपते हैं। 'सबकी खबर लें, सबकी खबर दें', 'नो कोर्से न जाने, नहो जनाएँ' का दौर खत्म हो गया। खबरें नाकसरतमक (निगेटिव) ही होती हैं, साकारात्मक (पॉजिटिव) कभी नहीं, वह मान्यता थी और अब ठीक उल्टा है। 'पेड न्यूज' शुरू हो गया है। कई संवादकों ने तो इसका विरोध किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो 'पेड पेज' व 'पेड पेपर' का चलन हो चुका है। ऐसी हानाहत में जोखिम लेकर कुछ ही अखबार और पत्रिकारें अपने चरित्र और स्वभाव को कितनी तरह बचा कर चल रहे हैं। टीवी चैनलों की भी स्थिति अखबारों-पत्रिकाओं ही जैसी है। उनको अलग नजरिये से नहीं देखा जा सकता।

गौरालब है कि पहले अखबारों-पत्रिकाओं को प्रेस कहा जा रहा था। जब टीवी चैनलों की बाढ़ आ गई तो प्रेस की जगह मीडिया शब्द का इस्तेमाल होने लगा। 'मीडिया' अब 'गोदी मीडिया' बन गया है। सोशल मीडिया का दौर है। गोदी मीडिया से निराश जनों को सोशल मीडिया से सहित मिल रही है। मीडिया जो काम नहीं कर पा रहा है, वह सोशल मीडिया कर रहा है, भले उसकी सीमा है। मीडिया को गोदी मीडिया बनाने की घाल को समझने, मीडिया के चरित्र और स्वरूप को बचाने के आंदोलन की जरूरत है। यह अभी संभव है जब इसके लिए आम लोग आगे आएँ।

गोप

बच्चों को तो बख्शा दो

मध्य प्रदेश की एक घटना यह है कि आठवीं कक्षा के एक दलित छात्र ने आत्महत्या कर ली। उसके हत्य का लिखा एक पत्रा मिला जिस पर उसने अपने स्कूल के शिक्षकों पर कई आरोप लगाए हैं। आरोप यह कि उसके शिक्षक जाति के आधार पर उसे तरह-तरह से प्रताड़ित करते हैं। हमें 'समता मार्ग' से यह जानकारी मिली। यह एक वेब पोर्टल है।

अमित प्रजापति नामक दलित छात्र सीधी जिले के रामपुर (सैकिन) थाने के तहत पट्टादूरी गांव का रहने वाला था। वह नवोपविद्यालय, घिरहुट सरा का छात्र था। उसके परिवार के लोगों का कहना है कि अमित को नौवीं जाति का बता कर दुर्व्यवहार किया जाता था। स्कूल के शिक्षकों का तर्क है कि वे अच्छी तरह से पहने-लिखने के लिए केवल छोट-छोटा करते थे। स्थानीय प्रशासन इस घटना को जांच कर रहा है। बाद में पता चला कि राजस्थान में शिक्षक द्वारा एक दलित छात्र को बुरी तरह मारने-पीटने की घटना हुई थी। छात्र का कसूर यह था कि उसने स्कूल में राखे घड़े से पानी ले कर पी लिया था। उसे इतना मारा-पीटा गया कि वह अचमरा हो गया और उसके परिवार वालों को उसकी जान बचाने के लिए उसे

अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्कूल के शिक्षकों ने इस घटना को सिर से इनकार किया और प्रशासन ने जांच करने का भरोसा दिया।

दलित युवकों को साइकिल पर या घोड़ी पर चढ़ने या सज-धज कर रहने पर प्रताड़ित करने, उसे मारने-पीटने, झूठे आरोप लगा कर, नंगा कर सामूहिक पिटाई करने, मोटर साइकिल में बांध कर घसीटने, दलित पुरुषों के साथ छेड़खानों और बलात्कार करने की घटनाएं अखबारों में देखने को मिलती रहती हैं। अब स्कूली बच्चों के साथ भी जुल्म की घटनाएं होने की खबर आने लगी है। यहां यह भी निरुत्तर कर देना जरूरी है कि ऐसी घटनाएं होती हैं बहुत, लेकिन कुछ का पता कभी-कभार ही चल पाता है। अधिकतर घटनाएं दबा दी जाती हैं।

जब समाज में मनुवादी ताकतें ताकतवर होने लगे और विषमता का सबसे बड़ा आयाम जातीयता उभारी जाने लगे, तो ऐसी घटनाओं का होना अस्वाभाविक नहीं है। ऐसी घटनाओं का जितना विरोध होना चाहिए, नहीं हो रहा है। सामाजिक आंदोलन न होना इसको बड़ी वजह है।

जोशीमठ के ध्वस्त होने का मतलब

जोशीमठ अब पहले जैसा नहीं है। यह शहर धंस और बर्बाद हो रहा है। जहां के लोग शरणार्थी बन गए हैं। जानकार बताते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरा करने के लिए ही रहे निर्माण कार्य के दौरान जोशीमठ के धंसने का रिकॉर्ड शुरू हुआ और यह मिलसिला काज खत्म होगा, निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्माण कार्यों के चलते उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों को ऐसी बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। वैज्ञानिक व प्राकृतिक दृष्टि से मनुष्यों को नजरअंदाज कर 'विकास' का दिखावा और निर्माण कार्य किया जा रहा है।

कहना न होगा कि सरकार और प्रशासन की ओर से पर्यावरण की रक्षा करने के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। उसके साथ नाइलाफी हो रही है। प्रकृति से जबरजस्ती को जा रही है।

पहाड़, जंगल, जमीन, वन, नदी, झील, समुद्र से वर्षावर्षण बनता है। पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जंगल काटे जा रहे हैं। जमीन अनुपयोगी बनाई जा रही है। वन खत्म किए जा रहे हैं। नदियों पर बड़े-बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। नतीजतन पहाड़ों का धंसना, अचानक घोंसम बदलना, बादल फटना, जलस्तर का नीचे जाना, नदी सूखना, झील का फटना, बाढ़, सूखा जैसे संकट बढ़ने लगे हैं।

गांव को उखाड़ कर शहर को आबाद किया जा रहा है। शहर की चमक-धमक के लिए पर्यावरण की उपेक्षा हो रही है। शहर पर अंकुश नहीं लगाया गया, पर्यावरण विरोधी शहरी मानसिकता को नहीं बदला गया, मौजूदा तथाकथित विकास को नहीं त्यागा गया तो विनाश को रोक नहीं जा सकता।

—सर्वादिक

सामयिक वार्ता की यात्रा

अतुल कुमार

सामयिक वार्ता का मोनूदा यह अंक आपके हाथ में है। इधर कुछ महीने से आपको कई अंक नहीं मिले होंगे, उसके पहले डाक से, साधियों के हाथों व ऑनलाइन भी मिलते रहे होंगे। कोरोना जैसे व्यवधान के चलते सामयिक वार्ता समय से आप तक नहीं पहुँच पाई। हमारी कोशिश है और हमें उम्मीद भी है कि सामयिक वार्ता समय पर आप तक पहुँचे। यह कहना अति न होगा कि सामयिक वार्ता देश में हिंदी में वैचारिकी प्रस्तुत करने का दुर्लभ माध्यम है। यह हमारे विचारों को समाजवार्ता कसौटी पर परीक्षण कर परिमार्जित करता है।

हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कलकत्ता (कलकत्ता) से सत्तर के दशक में प्रकाशित होने वाली चौरंगी वार्ता की ही कड़ों से सामयिक वार्ता ने उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है जिसकी कल्पना चौरंगी वार्ता के वक्त की गई थी। आपातकाल में चौरंगी वार्ता पर सरकार की कुदृष्टि और उसके प्रकाशकों, संचालकों, लेखकों और उससे जुड़े महत्वपूर्ण जनों के जेल में चले जाने के बाद वह बंद हो गई। आपातकाल के बाद 1977 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की शुभकामनाओं के साथ सामयिक वार्ता का पटना से प्रकाशन शुरू हुआ।

पटना से सामयिक वार्ता का प्रकाशन स्वर्णकाल कहा जा सकता है। संपादक किशन पटनायक और संपादन कार्य संभालने वाले अशोक सेकसरिया के हाथों यह पत्रिका चमक रही थी। इस हजार से ज्यादा प्रतिष्ठा पाठकों के हाथों में पहुँच रही थी। लेकिन कुछ वर्षों बाद हालात ऐसे बने कि उसे 1984 में वाराणसी ले जाना पड़ा। यहां साधियों के सहयोग से यह अपने असरदार व उज्ज्वल रूप में प्रकाशित होती रही। वाराणसी में रहते सामयिक वार्ता ने नए-नए साधियों को जोड़ा ही, अपनी वैचारिकी को भी तेवर के साथ धार दिया।

तब समता संगठन का गठन हो चुका था और किशन पटनायक की आगुवाई में इसके नेता-कार्यकर्ता वैकल्पिक राजनीति का आकार देने का उद्यम करने लगे। सामयिक वार्ता इस वैकल्पिक राजनीति के वैचारिक पक्ष का मुखपत्र और वाहक बन गई थी। इस दौर में सामयिक वार्ता ने अनेक ज्वलंत मुद्दे उठाए और अपनी राय रखी। पंजाब का ऑपरेशन ब्लूस्टार, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या, सिख विरोधी दंगे और देश भर में उसका असर, इंदिरा स्मृतिभूति के बल कांग्रेस को बहुमत, उसकी सरकार के दौर में अपनाई गई नीतियों पर सामयिक वार्ता ने बड़ी संजीदगी और गंभीरता से घंटाक पिशलेवण किया और वैकल्पिक राजनीति वास्तव समाजवादी नेताओं-कार्यकर्ताओं को दिशा दी।

सामयिक वार्ता को 1989 में वाराणसी से मुजफ्फरपुर ले जाया गया। बिहार के इस एक छोटे शहर में इसका व्यापक स्वागत हुआ। उसे अनेक नए सहयोगी और वैचारिक समूह मिले, जिनके सहयोग से उसने अपने तेवर और धार को बरकरार रखा। एक खास बात यह भी थी कि समाजवादों विचारक सच्चिदानंद सिन्हा का सानिध्य प्राप्त हुआ। सामयिक वार्ता से जुड़े समाजवादियों का समूह देश भर में फैले अनेक समूहों को इकट्ठा करने में लग गया और इसी दौर में वैकल्पिक राजनीति के मद्देनजर जनानंदोलन समन्वय समिति का उदय हुआ, जो इस वैकल्पिक राजनीति को संसदीय राजनीति के मैदान में दल बना कर उतारने के लिए तत्पर हुआ। जनानंदोलन समन्वय समिति ने इस दौर में नीति निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, जिसकी धरातल पर आखिरकार 1995 में समाजवादी जन परिषद नामक राजनीतिक दल बना। इस पूरे दौर में सामयिक वार्ता पूरी प्रक्रिया की वाहक बनी और

हर पक्ष को सामने रखती रही।

सामयिक वार्ता जनवरी 1994 तक मुजफ्फरपुर से हो प्रकाशित हुई। उसके बाद उसे वाराणसी ले आया गया। वह यहाँ से 1998 तक प्रकाशित होती रही। चौरंगी वार्ता की तरह सामयिक वार्ता के प्रारंभ से जो एक बात अनवरत और एक लय में चलती रही, वह था अशोक सेकसरिया का अभिभावकत्व। वे सामयिक वार्ता को संभालने के लिए पटना आए, तो वाराणसी और मुजफ्फरपुर में नहीं रहते हुए भी कलकत्ता से ही उसे संभालते रहे।

सामयिक वार्ता 1998 में दिल्ली आ गई। आधुनिक साजसज्जा, तकनीक के साथ वह नियमित प्रकाशित होती रही। इसके कई ऐसे अंक निकले जिन्हें आज भी याद किया जाता है। कई बार इसे इतनी बेचारागी के साथ गुजरना पड़ा कि बिल्कुल अनाथ और निरौह सी लगी। अगर पटना को उसका स्वर्णम काल कहा जाए तो दिल्ली में सबसे नीचले पाथदान तक आने का रिकॉर्ड रहा। सामयिक वार्ता 2012

इंटरसी से प्रकाशित हुई।

इंटरसी में कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सामयिक वार्ता के अहम अंक निकले। यहाँ उसके कलेक्टर और साज-सज्जा में शानदार बदलाव हुए, साथ ही वह मासिक को बजाय द्विमासिक हो गई। तकरौबन दो ही साल हुए होंगे कि सामयिक वार्ता को संभाल रहे सुनील का 2014 में निधन हो गया। इस स्थिति में उसे वाराणसी लया गया। इसी बीच उसके स्वामी प्रकाशक राजेंद्र बिंदल गुजर गए। सामयिक वार्ता वाराणसी में 2019 तक चली। इसी साल वह फिर दिल्ली आ गई। स्वामी-प्रकाशक व संपादक को कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर उसका एक अंक निकला था कि देश-दुनिया कोरोना जैसी महामारी को घेरे में आ गई। इस महामारी में ही उसके डिजिटल तरीके से कई महत्वपूर्ण अंक निकले। महामारी का दौर खत्म हो गया है। समाजवादी विचारधारा को वाहक इस पत्रिका को पहले की तरह प्रभावशाली बनाने के लिए पाठकों-लेखकों की हर सहयोग को जरूरत है।

आधुनिक टेक्नोलॉजी ने समाचार पत्रों तथा दूसरे संचार माध्यमों को क्षमता बढ़ा दी है। कोरोडों-अरबों लोगों को अभिव्यक्ति का ठेका एक समाचार पत्र ले सकता है। ऐसे समाचार पत्रों का संचालन सिर्फ सत्ताधारी या पूंजीपति कर सकते हैं। संचालन और अभिव्यक्ति – इन दो शब्दों का कुछ लोग एक ही अर्थ लगाते हैं। संचार आसान हो गया है तो कहते हैं अभिव्यक्ति आसान हो गई है। बात उलटी है। संचार माध्यमों के द्वारा सिर्फ उन सारे लोगों की अभिव्यक्ति बनी रहेगी, जिनको संचार माध्यमों के मालिक चुन लेंगे। बड़े समाचार पत्रों ने छोटे पत्रों को अभिव्यक्ति छीन ली है। अब जो स्थानीय पत्र होते हैं, वे बड़े पत्रों के स्थानीय संस्करण जैसे ही होते हैं। अलग अभिव्यक्ति हो नहीं सकती। पुरानी टेक्नोलॉजी में यह संभव था कि सत्ता में रहे बगैर भी समाजवाद, साम्यवाद, ग्रामोद्योगवाद, नास्तिकवादी दृष्टिकोण की पत्रिकाएं समाज में प्रतिष्ठित हो सकती हैं। अब सिर्फ अपने समर्थकों के बीच ही उनका वितरण सीमित रहता है। तात्कालिक राजनीतिक प्रश्नों को छोड़ कर हर चीज पर सारे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों का स्वर एक जैसा होता है।

—**किसान पटनायक, अक्टूबर 1988 (विकल्पहीन नहीं है दुनिया से साधार)**

हमारे सपने और भूलें और अब 2024 के आम चुनाव की चुनौती

महेश विक्रम

आजादी के लिए संघर्ष के साथ ही एक परंपराग्रस्त रूढ़िवादी समाज के मानसिक परिवर्तन की अपेक्षा और उद्देश्य से हुए महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर और अनेक समाज और राष्ट्रचिंतकों और नेताओं के प्रयास एवं आंदोलन से हम सभी माथने में एक जागरूक समतावादी और सहिष्णु राष्ट्र के निर्माण का स्वप्न देखा था। आजाद भारत का संविधान उसी स्वप्न को आकार देने का घोषणा पत्र है। इसमें हमारी उत्कृष्ट सांस्कृतिक परंपराओं को संजोए रखते हुए आधुनिक शिक्षा के स्तर और एक सुनियोजित आर्थिक वातावरण के साथ एक आत्मनिर्भर और सक्षम राष्ट्र के निर्माण का कल्पना निहित थी। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित और उपेक्षित समूहों और समुदायों का लक्ष्य कर उनके उत्थान के विशेष प्रयास भी इसमें सम्मिलित थे। परंतु इसके लिए इन सभी उपक्रमों की पर्याप्तता और सधन सतत प्रयास और कार्यक्रम सभी कुछ होना अनिवार्य था। और सबसे बड़ी आवश्यकता थी उस दिशा में सत्त्वनिष्ठ जिजिविषा का बना रहना।

लेकिन हुआ क्या! हमारे आधे-अधूरे प्रयासों और फिर हताशाओं से ग्रस्त होते हुए कठिन परंतु वास्तविक पथ से विचलन और शार्टकट सरल मार्ग अपनाए जाने ने स्थिति को और जटिल बना दिया। हम पूंजीवाद के छद्मपूर्ण जाल में जा फंसे। थोड़ा पीछे जाए तो महात्मा गांधी द्वारा साध्व के लिए साधन की पवित्रता के अदृश के समानांतर समाजवादी अंतरविरोध से उपजित सचिन सान्याल, चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के उप क्रांतिकारी प्रयासों का भी अपना अलग वजूब बना रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही गांधी के आदर्श से प्रेरित समाजवादियों

ने कांग्रेस में भीतर ही कांग्रेस सोशलिस्ट समूह (1933) का निर्माण कर लिया था। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना अलग रास्ता चुन लिया। आजादी प्राप्त होने के साथ ही अपने समाजवादी राष्ट्र के स्वप्न को सत्ता की चौकट तक पहुंचाने के लिए गांधीवादी समाजवादियों ने नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश, एसएम जोशी, अशोक मेहता, युसूफ मेहर अली, राममनोहर लोहिया आदि के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग होकर अपना अलग दस्त बना लिया। समाजवादियों का संविधान सभा में शामिल न होना कितना उचित था या नहीं, वह प्रश्न हमेशा विचारणीय रहेगा। लेकिन राष्ट्र के नवनिर्माण के विषयों का भीति निर्देशक सिद्धांतों तक ही सीमित रह जाना इसका प्रकट परिणाम कहा जा सकता है।

तथापि हमारे संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना तथा विचार और वाणी की स्वतंत्रता एक बड़ा कदम था। जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण हेतु उठाए गए सीमित समाजवादी कदमों के रूप में दलितों का आरक्षण, जमींदारी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के उपक्रम, वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक विकास के कुछ आधारभूत प्रयासों के महत्त्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन नेहरू को दक्षिणपथियों और मध्यममार्गीयों के बीच छोड़ना कितना उचित था। वह भी विचारणीय है। जयप्रकाश की निराशा उन्हें संन्यास मार्ग की ओर ले गई और उनका सामान्यवादी स्वप्न भूदान और सर्वोदय आंदोलन तक सीमित हो गया। समाजवाद को भारतीय संदर्भ में कहीं अधिक गहराई से व्याख्यायित करने वाले पंचास और साठ के दशक के सर्वाधिक प्रखर समाजवादी चिंतक और नेता राममनोहर

मोहिया की अधीरता नेहरू-कांग्रेस विरोध पर आधारित होती गई और उनके गैर कांग्रेसवाद के नारे में मधुलिमये की असहमति के बावजूद हाशिए पर पड़े दक्षिणपंथियों को भी साथ लेकर सर्वोद सरकारों का प्रयोग और उनसे उपजित निराशाओं ने समाजवादियों के लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी। इंदिरा सरकार द्वारा प्रीवी पर्स की समाप्ति, बैंकों और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण समाजवादी दिशा में कुछ बड़े कदम जरूर थे। परंतु भ्रष्टाचार के प्रश्न से विचलित होकर आपातकाल की घोषणा एक बड़ी दुर्घटना बनी और राष्ट्र तानाशाही के संकट से ग्रस्त हुआ। इसी का बड़ा प्रतिवाद राजनीतिक संन्यास से जुलाए गए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति के नारे और युवा संघर्ष पाठानों के निर्माण में हुआ। इसने राष्ट्र को एक दूसरी क्रांति का भावसा दिलाया और जनता पार्टी की स्थापना के साथ एक बार फिर से समाजवादी दिशा में राष्ट्र के नवनिर्माण की आशाएं जगा ली गईं।

अनेक रूढ़िवादी मध्यममार्गी और समाजवादियों के बीच खोचतान का स्वाभाविक परिणाम केवल जनता पार्टी के प्रयोग की अफसलता हुई बल्कि इसने समाजवादियों के स्वप्न पर लंबे समय के लिए ग्रहण लगा दिया। मधुलिमये की अपेक्षाओं के बावजूद समाजवादियों का उसमें विलय आत्मघाती सिद्ध हुआ। समाजवादी पुनः कोई स्वतंत्र और स्पष्ट पहचान बनाने में विफल रहे। उनमें दुर्भाग्यपूर्ण बिखराव होता दिखाई दिया और इनके अनेक बड़े पंडित राजनीति और दिशाविहीन आंदोलन तक सीमित होकर रह गए। दक्षिणपंथियों को पुनः उभरने का मौका मिला। समाजवादियों द्वारा किसान संगठन, समता संगठन आदि के एकाकी आंदोलन जरूर चलते रहे लेकिन इसी बीच कमंडल का उभार और ठंकेल का आगमन राष्ट्र की एकता और संप्रभुता के लिए एक गंभीर संकट के रूप में प्रकट हुआ।

जनता पार्टी की दिशाहीनता के समय से ही आशंकित किशन पटनायक जैसे समाजवादियों ने इन्हीं चिंताओं का समाधान स्वतंत्र रूप से चल रहे जनआंदोलनों में खोजना चाहा और इसी उद्देश्य के साथ समाजवादी जन परिषद की स्थापना

हुई। पुनः जनआंदोलनों के समन्वय के प्रयास – एनएपीएम इसी का प्रतिफल रहे। दूसरी ओर हमारा लक्ष्यित मध्यम वर्ग और कारपोरेट आर्थिक उदारीकरण और वैधीकरण के दौर का हर संभव लाभ उठाने के लिए बंधन था। कारपोरेट के लिए दिशाहीन और मतिभ्रमित मध्यम वर्ग और हताश निराश आम जन को सांप्रदायिक नारों के साथ सत्ता पर काबिज होने की क्षमता रखने वाले दल के साथ खड़े होने में आसानी हुई। दक्षिणपंथी सांप्रदायिक राजनीति के उभार के कुछ अन्य समकालीन देशों और अंतरराष्ट्रीय कारण भी रहे हैं जिसमें समाजवादी आंदोलन का कमजोर पड़ना बड़ा कारण है।

वर्तमान संकट गंभीर है – देश भयंकर अधिक संकट में है। व्यवसाय धिखर रहे हैं। सार्वजनिक संपत्तियाँ और उद्यम – रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे यहाँ तक कि प्रतिरक्षा सामग्री का निर्माण भी, तेजी से निजी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। रोजगार नहीं है। महंगाई बेलगाम है। 80 प्रतिशत से अधिक जनता मुफ्त राशन पर निर्भर है। आयात-निर्यात का बेहिसाब घाटा और डॉलर के सामने रुपये का लगातार होता जवमूल्यन चिंतनीय है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का निजी हाथों में चलते जाना उनका देश के आम लोगों की पहुँच से बाहर होते जाना है। सरकारों सुरक्षा, संरक्षण और सुविधाएं सभी कुछ सत्तासीन दल के झूठे प्रचार और भाकंड भ्रष्टाचार का माध्यम बनी हुई हैं। देश को सीमाएं असुरक्षित हो चुकी हैं।

सांविधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं की अवहेलना और उनका दुरुपयोग आम हो चुका है। मोहिया सरकार का भ्रष्टाचार चुका है। सत्ताधारी दल और उसके सहयोगी करपोरेट



द्वारा कब्जा लिया गया है। विरोधियाँ और प्रश्न उठाने वालों के साथ देशद्रोहियों जैसा व्यवहार हो रहा है। अल्पसंख्यकों से दुश्मन और उनकी नागरिकता पर प्रश्न उठाने की बहुसंख्याधारित मुहोम राष्ट्र की एकता को भीतर ही भीतर तोड़ रही है। दलित, आदिवासियों, मजदूर, किसान और स्त्री सभी असहाय और अरक्षित हैं। नई पूंजीवादी शिक्षा नीति के विरोध तथा छात्र, मजदूर आदि के आंदोलन अत्यंत एकाकी या समाप्तप्राय हैं। शेर्जाब दल आत्मकेंद्रित और व्यक्तिवादी है। किसी समाजवादी राष्ट्रीय स्वप्न से उनका कोई लेना-देना नहीं है। किसान आंदोलन ने अवश्य ही कुछ मूलभूत प्रश्नों को उठा कर समाजवादियों और वास्तविक राष्ट्र चिंतकों में एक आशा जगाई है। लेकिन अब यह तय हो चुका है कि वर्तमान में सत्तारूढ़ दल को हटाने बिना पूरी तरह बेफटरी हो चुके हमारे राष्ट्र को पुनः किसी साकारात्मक दिशा में मोड़ना और इस भयानक संकट से उबारना बिल्कुल संभव नहीं होगा

जबकि स्वयं संविधान का बना रहना भी संदिग्ध है।

इसी संकट और चुनौती के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ चुका है। तो समता और धर्मनिरपेक्षता का स्वप्न संजोए रहते समाजवादी शक्तियाँ अब क्या सोच रही हैं? इस संकट की भयावकता को ध्यान में रख कर क्या वह स्वयं कोई बड़ा जनांदोलन खड़ा कर सकती है? जनता को अपने किसी क्रांतिकारी लेकिन यथार्थपरक घोषणा पत्र से अपने पीछे आने का आह्वान कर सकती है? अथवा, वर्तमान में व्याप्त जनांदोलनों से कई संगठनात्मक संस्कार बना सकती है? अथवा, अपने वैशिष्ट्य और अस्तित्व को संभाल कर रखते हुए अभी अधूरे समय पर ही आधारित किसी तात्कालिक लेकिन प्रभावी राजनीति विकल्प (दल या दलीय गठबंधन) और उनके अभियानों की सहयोगी बन सकती है? समाजवादी राष्ट्र भक्तों को वह अभी सोचना होगा और उसके कुछ प्रभावी और यथार्थपरक उपक्रम भी करने होंगे।

लंबे समय तक व्यापक वर्ग संघर्ष जाति व्यवस्था की आंशिक किंतु कारगर काट पैदा कर सकता है। वर्ग संघर्ष बहुत संकीर्ण भी हो सकता है क्योंकि वर्ग जातियों की तरह अनेक हैं। सही सोच और लंबी राजनीति के साथ अगर कोई किसान संघर्ष शुरू हो तो वह ऐसा व्यापक दीर्घकालीन संघर्ष हो सकता है। दूरभाष से समाजवादियों और गांधीवादियों के किसान आंदोलन अल्पकालीन रहे हैं और कम्युनिस्टों के आंदोलन इस कदर संकीर्ण रहे कि किसानों का एक बड़ा वर्ग उनसे बाहर ही रहा। मजदूर आंदोलनों या संकीर्ण किसान आंदोलनों में देश या समाज को शामिल करने की जरूरत नहीं होती। ये आंदोलन देश या समाज के दूसरे पहलुओं को प्रभावित किए बिना पूरे आंदोलन के साथ जारी रह सकते हैं। जबकि एक व्यापक किसान आंदोलन पूरे ग्रामीण समाज को अपने में समेट लेगा और उसकी जगह से पुराने सामाजिक-सांस्कृतिक ढाँचे में बदलाव होगा या आंदोलन अधूरा ही खत्म हो जाएगा।

-किरान पटनायक, समता एरा विशेषांक, जनवरी-फरवरी-मार्च 1984
(संभावनाओं की तलाश से साभार)

नफरत की राजनीति और स्त्री प्रश्न

निशा शिवूरकर

औरत के अधिकार मुद्दा हमेशा धर्म, जाति और पितृसत्ता से जुड़ा रहा है। ये ताना औरतों के खिलाफ रहे हैं। पितृसत्ता सांप्रदायिक राजनीति का अभिन्न हिस्सा है। पितृसत्ता और सांप्रदायिकता का एकसाथ मिला कर औरतों का जीना मुश्किल कर देता है। औरतों के खिलाफ अत्याचार बढ़ते हैं। सांप्रदायिक दल सत्ता में आने के बाद पितृसत्ता का गौरवीकरण बढ़ता है। पिछले हाई सौ साल के प्रगतिशील आंदोलन के संघर्ष के कारण औरतों को समानता का अधिकार मिला। साल 2014 में देश की केंद्रीय सभा में भारतीय जनता पार्टी आई, तब से स्त्रियों के अधिकारों पर संकट निमाण हुआ है।

उत्तर प्रदेश के अजय सिंह बिष्ट संसद सदस्य रहे साक्षी महाराज जैसे लोग हिंदू समाज के औरतों को ज्यादा बच्य पैदा करने के लिए खुले आम संवोधन कर रहे हैं। इसी तरह की अपील जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने नाज़ीवाद के नाम से किया था। ऐसा स्थिति में औरतों को सिर्फ बच्य पैदा करने की भर्जान के रूप में देखा जाता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति, सोचने, समझने वाले व्यक्ति के रूप में औरतों को देखा देने के विचार को अस्वीकार करने का माहोल खड़ा किया जाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सितंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में जनवरी अगस्त 2021 में आयोग के तरफ आए महिला हिंसाचार के मामलों की संख्या प्रकाशित किया है। साल 2020 की तुलना में महिला अत्याचार की घटना 46 प्रतिशत बढ़ गई है। इसमें आधी घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं। इसी काल में महिला आयोग के पास 19 हजार 953 मामले दर्ज हुए। साल 2020 में यह संख्या 13 हजार 618 थी।

धानजा के राज में महिला सुरक्षित नहीं, यह बमनूस्थिति नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। रॉयटर्स लंदन यह वृत्त

संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में दत्तात्कार की 40 हजार मामले दर्ज हुए। साल 2012 की तुलना में 60 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

सबसे दुखद बात यह है कि साल 2014 के बाद दत्तात्कार करने वाले अपराधी के समर्थन में धानजा नेता, मंत्री गण रास्ते पर आए। कश्मीर के कबुआ गांव में हुए छांटों बच्चों के साथ अत्याचार की घटना के बाद हिंदू एकता मंच ने अपराधी के समर्थन में मोर्चा निकाला। उस मोर्चा में उस समय के मंत्री लालामंग और चंद्र प्रकाश गंगा शामिल थे। उज्जैन, हाथरस की घटना के बाद भी यही हुआ।

हमारे देश में साल 2014 के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यह सत्ता और धर्मोद्धता का परिणाम है। देश के सामने बहुत बड़ा सांस्कृतिक संकट खड़ा है। इसका मुकाबला देश के लोकतांत्रिक समाजवादी विचारों के लोगों का साथ मिल कर करना चाहिए।

पिछले कई सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रभावित संगठनों की आर स देश में लव जिहाद, गोपंश रक्षा कानून तीन नलाक, समान नागरिक संहिता, मंदिर मसजिद, हिजाब आदि खिस्का को लेकर देश में मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों को खिलाफ नफरत फैलाने का षडयंत्र खड़ा किया गया है। मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। लव जिहाद और गोरक्षा कानून के नाम पर हिंदू जनजागरण सामाजिक बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आदि संगठन के हाथ में हथियार दिया गया है। नफरत की राजनीति ने झुंड को कानून को हाथ में लाने को छूट दी है। सत्ता का इस झुंड को समर्थन है।

विदेश की राजनीति का सबसे बड़ा खतरा स्थिती पर है। फरवरी 2022 में 'बुली बाई अप' और 'सुकी डिलस अप'



की बात सामने आई राजसूना के खिलाफ बिना डर साहम से लिखने वाली, बात रखने वाली लेखिका, कलाकार मुस्लिम समाज की धमशील औरतों के फोटो प्रदर्शित करके उनकी ऑन लाइन नीलामी का ऐलान किया गया। औरतों को जलोल करने का उनके स्वाधमान को ठेस पहुंचाने का यह घृणित अपराध है उसी तरह विभिन्न धर्मों में नफरत फैलाने का कारनामा है औरतों का दुख और वंदना देना अपराध है। इस अपराध में 18-21 के पढ़न वाले छात्र भी शामिल हैं इन छात्रों ने सोच समझ कर मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के ठेस पहुंचाई है। यह बड़ा बड़बुरा है। इसके पीछे हिंसा की राजनीति है हमारे देश के सांवेधानिक संरचना के सामने यह संकट है।

साल 2002 में गुजरात में हुए दंगे के दौरान अहमदाबाद में भीड़ ने पांच महोने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया था उसकी तीन साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस अन्याचार के खिलाफ बिल्किस बानो लड़ी ग्यारह दांको व्यक्तियों को सीवीआई की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कुछ महीने पहले गुजरात सरकार ने सज्जदाफत व्यक्तियों को रिहाई का निर्णय लिया। जेल से बाहर आने के बाद अपराधियों को फूलमाला पहनाई गई। फिटवाई बांटी गई बिल्किस बानो फिर से असुरक्षित हो गई है मामला

अभी सत्राध्य न्यायालय में चल रहा है। अपराधो खुल आम घूम रहे हैं।

कर्नाटक का हिजाब का मामला, कई राज्यों में बन रहे तब जिहाद के कानून नफरत फैलाने के हथियार बन गए हैं तीन तलाक के नाम पर मुस्लिम औरतों को सुरक्षा देने का बहाना बना रही मोदी सरकार के राज में देश की सभी धर्मों की औरतें असुरक्षा का अनुभव कर रही हैं।

मजहब के नाम पर स्त्रियों का बंटवारा शुरू है काई मजहब आपस में घैर करना नहीं सिखाता महिला चाहें किसी धर्म की हो, वह सहष्णुता और शांति के बानावरण में हो निश्चय हाकर रह सकती है। सभी धर्मियों की एकता और धर्म निरपेक्षता नारो मुक्ति आंदोलन को बल देता है।

हमें महात्मा गांधी के दिखाए पथ पर चलना चाहिए। गांधी जी ने कहा था 'अगर महिलाएं खुश और शांति से रहना चाहती हैं तो उन्हें अपनी जानि और धर्म से परे जाना चाहिए। एक ही भगवान ने हम सब को बनाया है। सभी स्त्री पुरुष इस देश के देश के नागरिक हैं महिलाओं का अपन धर्म को मानवता की कमीटी पर कसना चाहिए ' यही हमारी दिशा होनी चाहिए आज के सांप्रदायिक और नफरत फैलाने वाले माटोल से महिलाओं को मिल कर लड़ना चाहिए। यह महिलाओं की जिम्मेदारी है। तभी वे अपने घरों बच्चों और देश को बचा सकते हैं।

आदिवासियों का संकट

रंजीत कुमार महली

झारखंड में इरान की राजनीति धम्मने का नाम ही नहीं ले रही है। इस राज्य के बनने के पहले से ईसाई मिशनरियों को आदिवासियों के लिए खतरा बनाया जाता रहा है और आज भी यही बनाया जा रहा है। इस राज्य के मुस्लिमों के विरोध में आदिवासियों को भड़काने के लिए लव जिहाद की तर्ज पर 'जमीन जिहाद' (लेड जिहाद) का शिष्टा छोड़ा गया है। जब संझारखंड बना, तब से एक नई बात यह देखी जा रही है कि आदिवासियों का हिंदू और हिंदुत्व का भव दिखाया जाने लगा है। राजनैतिक प्रयोजनों के निमित्त इस प्रकार का धार्मिक भयादोहन भविष्य में जारी रहने की ही संभावना है। एक प्रश्न यह भी है कि आदिवासियों को क्या सचमुच में ईसायत, इस्लाम और हिंदुत्व से ही खतरा है? इस संकट से क्या धर्मांतरण काफ़ी से नहीं निपटा जा सकता? या फिर कोई अन्य शक्ति है जो स्वयं अदृश्य

रहने हुए आदिवासियों के खिलाफ ईसायत, इस्लाम और हिंदुत्व को खड़ा करके अपना स्वायं साध रही है? ये सारे प्रश्न आपस में एक-दूसरे से गुंथे हुए हैं। साधव ही कोई यह इकार कर कि आदिवासी और आदिवासियों का संकट य है आज आदिवासियों के संकट या खतरों का स्वरूप बदल चुके हैं मौजूदा सवों में उनका सामना पूंजीवादी भौतिकवाद से है। यह पहल के सभी संकटों या खतरों से ज्यादा खतरनाक व घातक है। यह

अप्रकट और अप्रत्यक्ष है। यह अदृश्य संघर्ष आदिवासियों के शरीर से नहीं, मन-मनिक से लड़ी जा रही है।

पूंजीवादी भौतिकवाद या बाजारवाद आदिवासियों के घर पर विकास व भौतिकता के आकाश के रूप में दस्तक दे रहा है। आदिवासियों के लिए इसको समझना काफी मुश्किल है। आदिवासियों को कुछ युवजन समझने लग गए तो उन्हें भटकाने के लिए किसी समुदाय विशेष को उनके खिलाफ खड़ा करने में पूंजीवादी, बाजारवादी शक्तियां बड़े कांई गुरज नहीं। ऐसी शक्तियों की ही यह चालाकी है कि आदिवासी युवजन आदिवासी बनाम गैर आदिवासी स्थानीय बनाम बाहरी, मेरी भाषा बनाम तेरी भाषा के मसले में बं उलझें रहें। आगे भी जब ऐसी शक्ति को आदिवासियों से आंच आएगी तो वह इसी तरह के संघर्षशील मसलों को आगे कर अपना



बचाव करेंगे और धर्म की स्थिति पैदा करेंगी। आदिवासी समाज अपने शत्रुओं का जन्म कर और आखिर तक मुकाबला करने वाला समझा जाने वाला समुदाय बिना मुकाबला किए बाजारवाद से हार जाने वाला समाज कहा जाने लगेगा। यह कितना दुखद है कि आदिवासी नेतृत्व को दूसरे धर्म समुदायों से संभावित खतरे ना दिखाई पड़ रहा है लेकिन पूंजीवाद-बाजारवाद का खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। यह तो उनकी बाजारवाद के प्रति मौन स्वीकृति ही कही जाएगी

आदिवासी समाज में पिछले कई दशकों से जो पतन करने वाला बदलाव नहीं हो पाया था, पूंजीवादी-बाजारवाद ने वह महज दो सौन दशक में कर दिखाया है। पूंजीवादो-बाजारवाद आदिवासियों की जीवन शैली, जीवन मूल्य, इतिहास व दर्शन की उनकी अपनी समझ को तेजी से बदलते रहने में कामयाब होता नजर आ रहा है। जनजातीय भाषाएं दम नाड़ रही हैं, कई जनजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, असुर बिरहोर तो नाम के लिए बचे हैं। आदिवासी सारंगो बजाते हुए अहो बूटी बचने नहीं दिखते। मालार समुदाय द्वारा गंदना गोदने का काम अब आधुनिक ट्रेड बाजार में छीन लिया है। परंपरिक कला और उससे संबद्ध धंधे बाजारवाद के सामने टोक नहीं पा रहे हैं। समझ के साथ कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। अर्थशास्त्रोय भाषा के मुताबिक यह बाजारवादी अदृश्य बेरोजगारी है। झारखंड में असुर बिरहोर और मालार समुदाय की विलुप्ति धमांतरण की वजह से नहीं, बाजारवाद की वजह से है। पूंजीवादी बाजारवाद आदिवासियों को मूल समाज और जीवन से वंचित कर रहा है।

उदारीकरण की वजह से आदिवासी समुदाय की प्राकृतिक निर्भरता सीमित होती जा रही है और उसकी जगह पर बाजारवाद उन पर हावी हो रहा है। यों कहीं को वे प्राकृतिक क्षेत्र से विस्थापित किए जा रहे हैं और बाजारवाद के संयुक्त में फंसने के लिए बाध्य हो रहे हैं। बाजारवाद उनके लोक मान्यताओं और त्योहारों का प्रभावित करने लगा है और उनके लोक व्यवहार व लोकचरित्र में बदलाव आने लगा है।

अहं सादगीपन से उपभोक्तावाद के दलदल में तेजी से ढकला जा रहा है। बाजारवाद की मंशा आदिवासियों का शासन और आदिवासियों का विनाश की है। ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि आदिवासी प्राकृतिक उत्पादों पर निर्भर नहीं रह सके बल्कि ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद के उपयोग के लिए मजबूर हों। उन्हें देशी ज्ञान और निज भाषा से अलग-थलग कर विदेशी ज्ञान और भाषा की होड़ में डाला जा रहा है। बर्थंड, मैरेज एनिवर्सरी, पिकनिक, गिफ्ट कल्चर को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। समारोहों में लोक गायन व दूसरी परंपराएं आधुनिक डीज, माइक, फिल्मी गाने, टैट, बैंड बुक, क चलन के आगे दबी जा रही हैं। धिंधा की बात तो यह भी है कि आदिवासी भी इन चीजों से इतने प्रभावित हो रहे हैं कि अपनी अच्छी चीजों का बाह्यगत मानने लग गए हैं। आदिवासियों तो जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिभावान आदिवासियों को भुनान बाबत उनका इस्तेमाल बाजारवाद का बढ़ावा या प्रभावशाली बनाने के लिए धड़न्ले से किया जा रहा है। राजनीति में तो पहले से हो रहा है। प्रतिभावान आदिवासियों का नामा की लंबी सूची है। बाजारवादियों की नजर आदिवासियों पर है और वे प्रतिभावान आदिवासियों का इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं। बाजारवाद के लिए विज्ञापन एक बड़ा औजार होता है। विज्ञापन में प्रतिभावान आदिवासियों के चेहरे दिखने लगे हैं और आदिवासी समाज उनका नाम भुनान पर रखने लगा है और उन्हें अपना आदर्श भी मानने लगा है। दूसरे शब्दों में कहें तो बाजारवादियों का आदिवासी समाज में प्रयोग कामयाब हो रहा है।

आदिवासी संस्कृति के आधार जल, जंगल और जमीन ही है। इनकी सुरक्षा में ही आदिवासियों की सुरक्षा निहित है। जल, जंगल और जमीन पर सबसे ज्यादा खतरा आधुनिक औद्योगिकीकरण और बाजार की भोगवादी संस्कृति से है। जिस चौथी औद्योगिक क्रांति की दुनिया और भारत में जोर शोर से चर्चा हो रही है वह आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित होने वाला है। आदिवासियों को इसके विरोध में पूरी ताकत से खड़े होने की जरूरत है।

समाजवादी जन परिषद का 13वां राष्ट्रीय सम्मेलन आभिमन्यु

संजय का 13 वां राष्ट्रीय सम्मेलन पटना में 2022 में 5-6 नवंबर को हुआ। कोरोना संकट के कारण तीन साल बाद यह सम्मेलन हो पाया। इसे 2021 में ही होना था।

पटना के रूकनपुरा में बिहार इलियन विकास समिति के परिसर में देश भर के परिषद के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पहले दिन झंड के आरोहरण, राष्ट्रगान और क्रांति गीतों के गायन के साथ सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। परिसर को परिषद के झंडे, बैनर और पार्टी के स्वर्गीय सचिवों मकसूद अली, डा. स्वर्णि, डा. संतू भाई, जगल किशोर रायबोर आदि के नाम पर तोरण-झारों व संघ के नामकरण से सम्मेलन में उत्साह का संचार हुआ।

उद्घाटन के बाद खुले स्वागत सत्र को शुरुआत आंदोलन के साथियों (राजकिशोर, बिबाधर और उषेन्द्र) द्वारा गाए क्रांति गीतों से हुई। इस सत्र में संजय के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में जन मुक्ति संघर्ष के झारखंड के वरिष्ठ साथी अरविंद अंजुम व मंथन साथ ही संजय के संस्थापक नेताओं में से एक स्वर्गीय किसान पटनावाक की पत्नी वाणी मंजरी दाम मंथ पर मौजूद थीं।

संजय का संगठन सचिव राजेश राय के संचालन के तहत सबसे पहले बोलते हुए संजय के निर्वाचन राष्ट्रीय महामंत्री अफलातून ने पिछले सम्मेलन से लेकर अभी तक के राजनैतिक घटनाक्रम का विश्लेषण करते हुए अपनी बात रखी। इस दौरान उभरे बड़े आंदोलनों और राजनैतिक प्रश्नों में से नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) के विरोध में शाहीन बाग आंदोलन और उससे प्रेरित संघर्ष की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं ने बिना किसी बड़े राजनैतिक दल के समर्थन के इस आंदोलन को मजबूत रखा।

हानाकि स्वतंत्र रूप से जिन लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया उनमें से कई जल गए और कुछ अभी भी जल में हैं। वहां दूसरी ओर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाकाने में जिन भाजपा नेताओं की स्पष्ट भूमिका थी, उन पर कोई कारवाही नहीं हुई। इसके अलावा किसान आंदोलन की जबरजस्त सफलता का जिक्र करते हुए अफलातून ने कहा कि इस ऐतिहासिक आंदोलन में सरकार को नए कृषि कानून का वापस लेने पर मजबूर किया।

अफलातून ने कहा कि दो बार से भाजपा ने अपने बल दूत पर कद्र में जो सरकार बनाई है वह मुख्य रूप से बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करती है। बंदरगाह, हवाई अड्डों के ठेकों से लेकर दालों आदि के व्यापार पर भी अड्डानी का एकाधिकार है जिसके निजो विमान पर वर्तमान प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अड्डानी के बड़े निवेश की योजनाएं व संभावनाओं के चलते वहां की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने अड्डानी पर सीधा हमला बंद कर दिया है।

लाकतंत्र के लिए चुनौती पेश करती हुई नीतियां में से इलेक्ट्रोरल बॉर्ड, जिसके तहत बड़ी राजनैतिक पार्टियां, विशेष कर भाजपा को चंदा देने वाला के नाम और राशि गुप्त रखी जा सकती है वहां अनैतिक और भ्रष्टाचार के सोल बताते हुए अफलातून ने इसका कड़ा विरोध किया। साथ ही कहा कि फिलहाल चुनाव में उम्मीदवार के खर्च की तो सीमा निर्धारित है लेकिन पार्टी के खर्च की कोई सीमा नहीं है। यह प्रावधान भी भ्रष्ट और सड़ी पूंजी के हित में है और इसे बदला जाना चाहिए। इसी तरह राजनैतिक दलों को बिना एकसीआरए के पालन के विदेशी चंदा लेने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने



संविधान संस्थापन करवाया था ता कि लोकतांत्रिक परंपरा क खिलाफ है।

सजप की ओर से चुनावों में फस्ट पास्ट ९ पोस्ट व्यवस्था की वजह अनुपातिक प्रतिनिधित्व को रखा रखते हुए, अफलातून ने उच्च शिक्षा को बरबाद और चर्चित वर्ग के लिए आरक्षित करने की सविनय अवज्ञा के तहत 57 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रवेश परीक्षा एकसाथ ऑनलाइन कराए जाने का उल्लेख किया, जो गरीब वर्ग के बच्चों के लिए मुश्किलें पैदा करती है।

उन्होंने आम बाल समय में पार्टी से सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने और आंदोलनों में बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी करने का आह्वान किया।

इसके बाद बोलते हुए सजप के बिहार के राज्य अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार ने स्थानीय इकाई की ओर से सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और पिछले तीन वर्ष में पार्टी के कामकाज का लेखाजोखा दिया। अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद हफ्ता सम्मेलन में नई ऊर्जा लेकर जाएंगे और संघर्ष तेज करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया।

इसके बाद विशेष रूप से अमर्त्य अरविंद अंजुम ने कहा कि वैकल्पिक राजनीति के संघ पर आकर ये प्रसन्न है। उन्होंने वर्तमान दौर को 'बेहम पूंजीवाद' के दौर के रूप में परिभाषित किया और उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड एलन मस्क का विक्रि किया जिसने ट्विटर का अधिग्रहण करते ही

एक चौथाई कर्मचारियों की छंटनी कर दी और बारह घंटे के श्रम दिवस की वकालत की है साथ ही गिंग श्रमिकों, जैसे खाना पहुंचाने वालों या ऐप के लिए टेक्सी चलाने वालों के शोषण पर ध्यान आकर्षित करने हुए उन्होंने कहा कि इनकी संख्या तीन करोड़ से ज्यादा हो गई है। लेकिन शोषण चरम पर है और मूलभूत अधिकारों और सुविधाओं से भी यह वर्ग वंचित है।

अरविंद ने भारत में आरएसएस के फासीवाद को हिटलर और मूसोलिनी से भी ज्यादा खतरनाक ठहराया क्योंकि यह संगठित

रूप में मौ से भी अधिक वर्षों से सक्रिय है और भयावह रूप धारण कर रहा है। चूंकि विचारधारा और दर्शन के आधार पर दमन ज्यादा खतरनाक है, उसके मुकाबल भी दार्शनिक स्तर पर करना होगा, ऐसा अरविंद ने कहा। उन्होंने याराना पूंजीवाद और याराना सांप्रदायवाद के व्यापक खतरे को भांपते हुए उसका मुकाबला आपसी मतभेदों से ऊपर उठ कर करने का आह्वान किया।

जनमुक्ति संघर्ष बाहिनौ के हो मंथन ने कहा कि आज हम भारतीय समाज के सकारात्मक तत्वों को उधारने की जरूरत है, जो सौ वर्षों से हमें हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने में सफल रहे। उन्होंने सांप्रदायिक और विषाक्त राजनीति को रोकने की जरूरत रेखांकित करते हुए व्यापक एकता बनाने की वकालत की। इसके तहत हम उन विदुओं का ध्यान करने को जरूरत है जिनके बल पर भाजपा को हटाया जा सकता है, जैसे राजगुरु, जालि का प्रश्न बहुजन एकता आपसोखकों की एकता आदि। यह काम हम 2024 के चुनाव में हो करना होगा और इसके लिए कमर कसनी होगी।

अर्थाथ वक्ता दायी मंजरी दास ने कहा कि एक देश एक भाषा जैसी नीतियों को थोपने पर देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और हिंदुत्व, हिंदू, मुस्लिम आदि पहचानों में भेदभाव करने की बजाय हम सभी को मानव मात्र मान कर व्यवहार करना चाहिए।

अध्यक्षीय वक्तव्य में सजप के निम्नलिखित राष्ट्रीय अध्यक्ष लिंगराज आजाद ने ज्ञात का भूमि के रूप में बिहार को संबोधित किया और याद किया कि कैसे बांधगया आंदोलन और संघर्ष खाहनी के साथ साझा संघर्ष ने उन्हें संघर्ष से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही दल के विकास में किशन पटनायक और बाणी जो के योगदान को उन्हां सामन रखा उन्होंने कहा कि जो समूह तात्कालिक सफलता के लिए काम करने हैं वे ज्यादा दिन नहीं टिकते, इसलिए सजप का दीर्घकालिक विचार लेकर चलना होगा। पार्टी का अपनी वैचारिक पुंजी का लकर अग्रे बढ़ना होगा और सत्ता की राजनीति के बरकस जनवादी राजनीति का झंडा बुलंद करना होगा

सत्र के अंत में संचालक रंजीत राय ने परिचर्चा का सार सम्मने रखते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया

अगले सत्र में निशा शिवरकर की अध्यक्षता में चंद्रभूषण चौधरी ने पार्टी का राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव सदन के सम्मने रखा। इस सत्र का संचालन नील चौधे ने किया प्रस्ताव पर परिचर्चा में भाग लेते हुए महेश विक्रम मनसंगांव, रंजीत राय, जोशी जैकब, शिवाजी गायकवाड़, इक्बाल अहिमन्तु, नीरज, जगनारायण महतां, गंगा प्रसाद, सुरेश नरिंकुज, शैलेश कुमार समेत कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी। चंद्रभूषण चौधरी ने प्रस्ताव में संशोधन बखत सुझावों टिप्पणियों का स्वागत किया और उन सुझावों टिप्पणियों में से कुछ का शाफल किया सदन ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया।

इसके बाद पार्टी ने शाक प्रस्ताव के तहत पिछले तीन सालों में जिन सदस्यों और सहमता साथियों का निधन हो गया था, उन्हें याद किया। इनमें उत्तर प्रदेश से डा. स्वाति, मकसुद अली, बिहार से डा. संतू भाई संत, अवध बिहारी शरण अजुन कुमार सिंह दिल्ली से प्रो बलवीर सिंह मध्य प्रदेश से श्रीमती उमा खरे, सुनील दुबे, संजय सिंह लाउन लाल मालवीय तृप्त दादा भूरे लाला मांझी और करल से केपी शाजी और मंगलडू राघवन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई

साथ ही पार्टी के आरंभिक दौर में जुड़े रहे संजीव साने, विश्वनाथ बागो और सामनाथ त्रिपाठी का भी याद किया गया

दूसरे दिन प्रथम सत्र में नीरज सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और सजप के आनुषांगिक संगठन किसान मजदूर संगठन को बैठक का उल्लेख किया जो सम्मेलन स्थल पर ही संपन्न हुई। इसके बाद प्रा. महेश विक्रम की अध्यक्षता में गंगा प्रसाद ने सजप का सामाजिक प्रस्ताव सदन के सामने रखा। इस सत्र का संचालन फागराम ने किया प्रस्ताव में हुई परिचर्चा में रंजीत राय, सिमता, जोशी जैकब, भारत भूषण, अफलातून, नौता चौबे अतुल राम दयाल, जगनारायण महतां आदि ने बात रखी और प्रो महेश विक्रम के अध्यक्षीय वक्तव्य के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

इसके अगले सत्र में पार्टी का आंतरिक चुनाव संपन्न हुआ जिसमें सर्वसम्मति से एडवाकट निशा शिवरकर को अगले दो साल के लिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और लिंगराज आजाद को राष्ट्रीय महासचिव चुना गया इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारणी के सदस्यों के रूप में कमल कृष्ण वनजी मॉलिन चंद्र वर्मन, रंजीत राय गंगा प्रसाद, अशोक रायवीर (पश्चिम बंगाल), अतुल कुमार और जगनारायण महतां (दिल्ली) शिवाजी गायकवाड़ (महाराष्ट्र), शैलेश कुमार, अफलातून, महेश विक्रम रामकेवल चौहान, नौता चौबे (उत्तर प्रदेश) नीरज सिंह, सुधांशु प्रसाद और नवल किशोर प्रसाद (बिहार), जोशी जैकब, कुरेश नारीकुजी (केरल) और विषाधर वैठारु (आंध्रप्रदेश) का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ चुनाव के तुरंत बाद हुई राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक में निम्न पदाधिकारियों को मनोनित किया गया। चंद्रभूषण चौधरी और रंजीत राय को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फागराम सुरेश नरिंकुज, अतुल कुमार और नीरज सिंह को राष्ट्रीय सचिव, जगनारायण महतां को कोषाध्यक्ष, अफलातून को संगठन मंत्री मनोनित किया गया।

संघर्ष को तेज और संगठन का मजबूत करने के संकल्प के साथ सम्मेलन छह नवंबर की शाम समाप्त हुआ।

सजप के राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित सजप का राजनीतिक-आर्थिक प्रस्ताव

सजप का पिछला राष्ट्रीय सम्मेलन जून, 2019 में हुआ था। अपने सर्वोच्चतम के मुताबिक सजप हर दूसरे साल अपना राष्ट्रीय सम्मेलन तथा अगले दो वर्षों के लिए पदाधिकारियों तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव करती रही है। लेकिन 2020 की जनवरी से शुरू कोविड-19 को वैश्विक महामारी तथा सरकारी प्रतिबंधों के कारण पिछले साढ़े तीन वर्षों में हम अपना राष्ट्रीय सम्मेलन और अन्य बैठकें सवह नहीं कर सकें। इसलिए इस सम्मेलन का संगठन के लिए बहुत महत्व है।

पिछले सम्मेलन से केवल दो सप्ताह पहले 2019 में लोकसभा तथा चार राज्यों के आम चुनावों के नतीजे घोषित हुए थे। इस चुनाव के नतीजों ने आजाद भारत के सभी चुनावों की श्रृंखला को तरह ही देश को दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली की खामियों को उजागर किया। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से बहुत कम 37,36 प्रतिशत वोट मिले पर लोकसभा में उस बहुमत से काफी ज्यादा 303 (54.71 प्रतिशत) सीटें मिल गईं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा केवल 31 फीसदी मत पाकर 82 सीटें (51 प्रतिशत) जीत कर संसद में बहुमत में आ गई थी।

यहां हम फिर एकबार दोहरा दें कि भारत में एफपीटीपी (फर्स्ट प्लेस्ट दी पोस्ट) - सर्वाधिक मत लाने वाले को अन्य उम्मीदवारों के सारे अधिकार मिल जाते हैं। चुनाव-प्रणाली चला रही है। सजप काफी पहले से ही इस चुनाव प्रणाली को जगह अनुपातिक चुनाव प्रणाली से लाने की मांग करती रही है।

तत्कालीन चुनाव सुधार बंद हमारी यह मांग जितने महत्वपूर्ण है। क्योंकि पिछले आठ वर्षों की घटनाएं यह सिद्ध कर चुकी हैं कि हमारी दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली देश के शासन का तानाशाही की ओर ले जाने का सबसे प्रमुख कारण है। इस चुनाव प्रणाली के कारण विश्व इतिहास में कई अन्य देशों में एफपीटीपी चुनाव द्वारा बने सरकारें तानाशाही में बदल गईं थीं। यथा हिटलर, मुसोलिनी

और वर्तमान में रूस की पुतिन की सरकार। इसी कारण दुनिया के नब्बे दशों में पिछले 80 वर्षों में अपनी चुनाव प्रणाली को अनुपातिक प्रणाली में बदल लिया है।

कोविड महामारी के कारण पिछले साढ़े तीन साल देश और दुनिया में कई कठिन चुनौतियों और अति दुखद हालातों का समय रहा है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान महानगर में कोविड-19 के संक्रमण की महामारी तब से फैली और बड़ा संख्या में गंभीर बीमारी और मौतों की शुरुआत हुई। चीन की सरकार ने महामारी को रोकने के लिए सभी मानवोद्योग गतिविधियों पर रोक लगा दी और जनता को अपने घरों में बंद कर दिया। साथ ही चीन सरकार ने महामारी के विषयों पर शोध कर उसको डीएनए संरचना को सारी दुनिया के लिए दिसंबर 2019 में ही प्रकाशित किया तथा संक्रमण रोकने के टीके के लिए शोध किया। इन प्रकाशनों के आधार पर दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने अपने देश की सरकार की आर्थिक मदद से टीका पर त्वरित शोध किया तथा ब्रिटेन की एस्ट्रा जेनिका, अमेरिका की फाइजर तथा मोडरना, जर्मनी की बायोएनटेक और रूस की स्पुतनिक वो वगेरह।

संक्रमण रोकने के लिए चीन और पश्चिमी देशों ने जनवरी 2020 की शुरुआत से ही अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर कई किस्म की जांच और रोक लगाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने 24 जनवरी 2020 को ही एक सलाह जारी कर सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के शरीर का तत्पमान नापने का कहा। 11 फरवरी की सलाह में बीमार पड़ गए यात्रियों को क्वारेन्टाइन करने का कहा गया। उस समय भारत में प्रति दिन आने वाले संक्रमित यात्रियों की संख्या दो चार ही रही होगी। लेकिन भारत सरकार ने इस महामारी को समझने और रोकने के मामले में पूरे नकार स्तर का अज्ञान और लापरवाही दिखाई। विश्व स्वास्थ्य

संगठन की चेतावनी के बावजूद महामारी के प्रति अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधानमंत्रियों मोदी की महामारी के प्रति सामंजस्य नकार, कहवाही लूटने का लालच और लापरवाही की पराकाष्ठा 24 फरवरी 20 का सत्रा लाख जनता की अहमदाबाद में 'नमस्ते ट्रम्प' रैली में हुई। बाद की जांच में पाया गया कि अहमदाबाद में सक्रिय पाए गए ज्यादातर लोगों ने उसमें भाग लिया था। रैली ने देश-विदेश में कर्वाँव बने फैलाने का गंभीर अपराध किया। भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय को मई 2021 में दिये गए अपन हस्तक्षेप में स्वाकार किया कि 'उमन कोविड के टीके के शोध के लिए कोई अनुदान या सहायता नहीं दी' पर बाद में सरकार और भाजपा अपनी तारीफ में यह कहती रही है कि पारस ने जल्द दो टीके बना कर विज्ञान में उन्नत देशों में अपनी जगह बना ली।

सरकारी लापरवाही से संक्रमण जब तजी से बढ़ा तो सरकार के हथ-पैर फूल गए। बिना किसी नैसर्गिक प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च 20 को शाम में अचानक पूरे देश में लालाबंदी (लॉकडाउन) की घोषणा कर दी। देश में खराब शासन और जन उत्पीड़न का यह सबसे बुरा चढ़ा था। इस लालाबंदी के कारण करोड़ों गरीब जनता खासकर प्रवासी मजदूरों का अपार तपीड़न और दुख झेलने पड़े। इन तथ्यों से सारा देश और दुनिया बाकफ है। विभिन्न स्वतंत्र अध्ययनों का निष्कर्ष है कि भारत में करीब 50 लाख लोगों की मौत हुई। पर सरकार उससे बहुत कम केवल पांच लाख मौतों के आंकड़े देती रही है।

एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार की ये पांच न्यूनतम कर्तव्य होते हैं। एक जल्द से जल्द देश में आर्थिक सामाजिक, इलाकाई और लैंगिक समता लाना। आमदनी और संपत्ति की गंभीर विषमताओं को घन कर फिर बंटवारा कर समत्व समता के अनुपात में लाना। दो, देश की सरहदों की सुरक्षा करना साथ ही अन्य प्रकार की सुरक्षा यथा ध्वजन, स्वास्थ्य शंजगार, प्राकृतिक आपदाओं से तथा ज्ञातिपूर्ण बतमान और भविष्य की सुरक्षा तीन, र्जाविधान में वर्णित धाराओं और संविधान की आत्मा के अनुरूप शासन चलाने के साथ ही जरूरी सामाजिक, आर्थिक प्रशासनिक और राजनैतिक बदलाव को नेजी से पूरा करना। चार, देश के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों की मदद करना। साथ ही देश का

संघीय स्वरूप बचाए रखना। शासन के लोकतांत्रिक विवर्द्धकरण के लिए जन तीन संविधान, 73 74 और 99 के पेशा (पीइसीए) कानून का प्रभावी बनाने में राज्य सरकारों को जरूरी आर्थिक और प्रशासनिक मदद देना पांच पूरी आधारों को अच्छी कृषि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा देने के लिए राज्य सरकारों को जरूरी संसाधन मुहैया कराना।

अब हम देखें कि इन पांच कर्तव्यों में केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले तीन-चार वर्षों में क्या और कैसे किया। भाजपा मोदी सरकार और तथाकथित बौद्धिक लाग भी भारत देश के मकल राष्ट्रीय अनाद (जीडीपी) को विकास के मानक के रूप में दाहगते रहते हैं। यह ध्यान में रखना है कि अभी विश्व में अपनी की डॉलर ही एकमात्र स्थिर मुद्रा है। इसलिए सभी आर्थिक आंकड़े उसी में बताए जाते हैं। अन्य सभी देशों की मुद्रा में कर्मावंश अंतर चढ़ाव होता रहता है इसलिए उनमें बांणन आंकड़ों में खड़ी गलती हो सकती है। आपने मोदी और भाजपा - विपक्ष के अन्य नेताओं से बार-बार ट्रिलियन शब्द सुना होगा। अभी भारत का जीडीपी करीब साढ़े तीन ट्रिलियन (साढ़े तीन लाख करोड़ डॉलर) है। जिसका विश्व में पांचवां स्थान है। सभी सरकारें इसकी वाहवाही लूटती रही है।

लेकिन इस प्रकार के दौरान बड़ी चालाकी से प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय पैदावार (अर्थात् प्रति व्यक्ति जीडीपी) का छिपा लला जाता है। देश की समृद्धि का सही सूचक यही होता है। भारत की विशाल करीब 140 करोड़ आबादी में औसत प्रति व्यक्ति सालाना आय केवल ढाढ़े हजार डॉलर है। जो करीब डेढ़ लाख रुपये होता है। धनी देशों में यह आय करोड़ 40 से 70 हजार डॉलर है। इस सीढ़ी पर भारत विश्व में 42 वें पायदान पर है। अर्थात् हम अति दरिद्रों की श्रेणी में आते हैं। चीन में यह आय हमसे सात गुणा ज्यादा है। बांग्लादेश भी विकास कर भारत से पांच पायदान ऊपर 137 वें स्थान पर आ चुका है। पड़ोसी मलेशिया और इंडोनेशिया भी हमसे ऊपर है।

अब हम अमीरों और गरीबों के बीच गैर बराबरी को देखें। देश में सबसे अच्छी आमदनी वाले ऊपर के 10 प्रतिशत लोग कुछ कमाई (वार्षिक आमदनी) का 57 प्रतिशत ले लेते हैं। वहीं कम कमाई वाले आधे (अर्थात् 50 प्रतिशत) लोगों को केवल 13 प्रतिशत ही मिलता है। सबसे धनी एक प्रतिशत लोगों का पास

राष्ट्रीय संपत्ति का एक तिहाई (33 प्रतिशत) है। मध्य वर्ग को शामिल कर सबसे धनी 10 प्रतिशत जनता के पास देश की तीन चौथाई से भी ज्यादा 77 प्रतिशत संपत्ति है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में वार्षिक अन्नमदनी और वृत्त संपत्ति की एक खाई हर एक स्थान बढ़ती ही रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने इसादन अपनी नीतियों से इस गैर बराबरी को बढ़ाया है।

केवल एक सेड गौतम अन्नानी मोदी सरकार से बार पुनोपत्ति का रिश्ता बना कर एक साधारण व्यापारी से उड़ कर दुनिया का दूसरा नोसरा धनी आदमी बन गया। उसको और अंबानी का सरकारी पुँजिया का उपहार मिन्न के बारे में आप सब विभिन्न स्रोतों से पढ़ते सुनते ही रहे हैं।

अब सेन्सेब (रामेश्वर) गैर बराबरी बने छेड़ें। राष्ट्रीय ओशन प्रति व्यक्ति सालाना दाई हजार डॉलर की आय

क मुकन्नलबले प्रांत आदमी जोड़ों में तीन सबसे गरीब राज्य है

बिहार सालाना 661 डॉलर

उत्तर प्रदेश - सालाना 934 डॉलर

झारखंड - सालाना 1081 डॉलर

इन राज्यों को जनता में भी अमीरी और गरीबी की आय में अभी पहले बसाई गैर बराबरी का अनुपात वैसा ही है। बिहार के सबसे गरीब तबकों के एक आदमी का सालाना करीब दो सौ डॉलर अर्थात् महीने में केवल 1300 रुपये में पूरा साल जीना होता है। इसको सुधारने वाले मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया बल्कि और बिगाड़ा है। आप सब जानते होंगे कि काबिड महामारी में हजार तकलीफ उठा कर घर लौट मजदूरों को अपने गांव-घर में भी बरामगारो और दुखद परिस्थित मिली। तुरंत ही वे सब वंचन होकर घर परिवार छोड़ बागस बड़े शहरों की तकलीफ भरी जिंदगी की ओर भागने लगे।

सरहदों की सुरक्षा में मोदी सरकार बिल्कुल झुठी और

नकारा साबित हुई है। पिछले चार वर्षों में भारत चीन सीमा के नदियां अरुणाचल और भूटान खड़ा में चीन की सेना द्वारा आगे बढ़ कर घुसपैठ भारतीय अवासों की हत्या कई तरह के निर्माण और पूरा गांव बसा देने की जग जाहिर घटनाएं होती रही हैं। मोदी सरकार चीन सरहद पर इन हमलों पर बयान देने से लगातार भागती रही है। कायदन कद सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री का इस पूरे मामले पर संसद में एक श्वेत पत्र लाना चाहिए था। पर

सरकार तालमटोल के बयान देती रही और उसका विशाल गादी पिडिया इस हाम में भी मोदी की बहादुरी का गुणगान करती रही।

अक्टूबर 20 9 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनापिंग और मोदी की ममलापुरम में गलतबाहियों के कवल सत महीने बाद चीनी सेना न गलवान में बिपत्ति क्रूरता में 20 भारतीय अवासों की हत्या की। अभी सितंबर 22 में मोदी फिर शी जिनापिंग से समरबंद में मिले पर चीनी सरहद पर कब्जे हुए

इलाक़े पूरे तौर पर लौटाने की कोई बातचीत नही हुई। अभी अक्टूबर 22 में हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े सम्मेलन में गलवान हमले के चीनी कमांडर का शामिल किया गया। उस शी जिनापिंग की बड़ी उपलब्धि बताया गया और हमले का वीडियो दिखाया गया।

एक तरफ चीनी सामानों का बहिष्कार करने की भावना नेताओं की खांखली अभील आती रही और दूसरी तरफ चीन से 90 अरब डॉलर का आयात अबाध चलता रहा। भारत द्वारा चीन को कवल 14 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। हमारा घाटा सालाना 75 अरब डॉलर।

भारत सरकार ने इसे पाटन और आयात-निर्यात का अनुपात कम करने के लिए क्या किया? याद रखें कि किसी एक देश पर ऐसी आयात निर्भरता अपने देश की सुरक्षा के लिए बहुत कमजोर कड़ी होती है।

भाजपा सरकार की अस्पष्ट योजना द्वारा फौज में नियुक्ति

जवानों की जगह केवल चार साल के लिए रंगरूटों की भर्ती करना देश को सुरक्षा में भीषण खतरा पैदा करेगा। रंगरूटों का युद्ध मोर्चे और संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों में तैनात करने के कारण चार साल बाद बिना पेंशन के फौज से निवृत्त दिया जाएगा। यो पीड़ित और अपमानित बेरोजगार युवा सारी गैरनीय सूचनाओं का आम कर देंगे। वैसी हालत में वं कांड भी देश विरोधी क्रम उठा सकते हैं

जनता को अन्य सुरक्षाएं देने में भी केंद्र सरकार निकम्मी और विफल रही है। विश्व भूख सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में 12 देशों में भारत की जगह बहुत नीचे 107 की है। खाद्य सुरक्षा के मामले में साल दर साल देश की हालत सुधर नहीं रही है एक प्रतिशत रोजगार रोजगार रोजगार के अनुसूचित देश में बेरोजगारी की दर 7.8 प्रतिशत है। अगर राज्यवार देखें तो इसमें भी बिहार (1.4 प्रतिशत) और झारखंड (12.2 प्रतिशत) ज्यादा हो खराब है। रोजगार पाए लोगों की मजदूरी या वतन इतना कम है कि उनमें भी ज्यादातर का बेरोजगार ही मानना चाहिए। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा 4.2 प्रतिशत लोग रोजगार पाते हैं छोटे कुटीर न्याय में कामने लोगों के रोजगार की संभावना है। पर उन्हें तो सरकारी नीतियों में मगर ही खाला है जो नियोजित हैं उन्हें भी भविष्य में काम में लगे रहने की कांड सुरक्षा नीति सरकार ने नहीं बनाई है।

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान बढ़ने की संभावना करीब निश्चित हो है बड़े श्लोकों में सुखा बाढ़ बढ़ने और समुद्र तटों के पानी में डूब जाने का बड़ा खतरा है। इन आपदाओं से जनता की सुरक्षा के लिए कांड प्रभावी नीति केंद्र सरकार ने नहीं बनाई है

मादो सरकार आदतन संविधान की धाराओं के तहत अथ पक्ष करती है, जो संविधान की आत्मा के विरुद्ध जाती है इसके लिए उसने विभिन्न सांख्यिक तथा अन्य संस्थाओं के चरित्र को लगातार बिगाड़ा है। इसमें संसद चुनाव आयोग, सीजेआई, ईडी एनआई, एनसीबी, रिजर्व बैंक, सरकारी विभागों का उच्च प्रशासन, राज्यों के राज्यपाल, सरकारी कंपनियां (उपक्रमों) बैंकों के उच्च प्रबंधकों, दिल्ली पुलिस, विश्व विद्यालयों कोरह सभी शामिल हैं

भारत की केंद्र और राज्य सरकारों ने सोबीआई ईडी

एनआई, राज्य पुलिस और एनसीबी द्वारा हजारों पत्रकारी विपक्ष के कार्यकर्ताओं-नताओं, बौद्धों, लखकों, समाजिक कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक अल्प नागरिकों पर बिना अचिन साक्ष्य के ही दमनकारी प्रावधानों के तहत मुकदमों लगाए गए और उन्हें जेल में बंद किया है यह पूरी बदनीयति से शरान का आतंक फैलाने के लिए किया जाता है किसी भी प्रदर्शन, धरना, सभा चरित्र के पहलू ही नताओं को घर में राका जाता है या हवालान में दिनभर बंद रखा जाता है। अल्पसंख्यकों और विपक्षी लोगों के घरों इफतरी और प्रतिष्ठानों के अकारण बलुडानों से खाल का गैर कानूनी अतिक्रमण का काम किया जा रहा है। निषिक्त मोड़िया अखबारों, इंटरनेट पोर्टलों पर छापे डाले जा रहे हैं, बैंक खालों रोकें जाते हैं और झूठे मुकदमों लादे जा रहे हैं। रोजगार मोड़िया में खाल केवल एक फ्रंट के लिए लोगों पर मुकदमों किए जा रहे हैं। साथ ही सरकार आईटी सेक्टर की निगरानी के लिए कानून बनाने से भाग रही है। लखर कोट व्यवस्था के कारण सालों साल उन्हें जमावत तक नहीं मिलती है। यहां सत्य के मित्र और सहकर्मी चौरामी वर्षीय फास्टर स्टैन स्वाामी की अकारण गिरफ्तारी जेल में उत्प्रेषण जमानत न देना और हत्या जैसी मौत का खारा उल्लेख करती है

सामाजिक न्याय के लिए जरूरी जातिवार जनगणना को नहीं करने पर भाजपा सरकार अड़ें हुई है संविधान न कानून व्यवस्था बनाने रखने का अधिकार मुख्यतः राज्य सरकारों को दिया है। इसमें उनको मदद करना और जरूरी संसाधन देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। पर भाजपा की केंद्र सरकार लगातार ये अधिकार अपने हाथ में लेकर राज्य सरकारों को और देश की संघीय व्यवस्था को कमजोर करती रही है।

तीन संविधान संशोधन - 75, 74 और 73 (पांडुरंग) राज्य सरकारों को जिम्मेदारी और अधिकार देते हैं कि व क्रमशः ग्रामीण, शहरी और आदिवासी क्षेत्रों में प्रदेश से नीचे स्तर पर लोकतांत्रिक निवृत्तों बनाएं और सुदृढ़ कर प्राप्त प्रखंड, निता पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम सभा वगैरह। राज्य सरकारें अपने अधिकारों और संसाधनों में कम हो जाती देख कर डरती हैं और नीचे को इकाइयों को मजबूत नहीं करती हैं समाज में बहुतरे मुखर लक्षण भी लोकतांत्रिक नृत्व को बढाना कर अफसरशाही और पुलिस राज को और मजबूत करने को

वकालत करने हैं

संजय के सामने यह चुनौती है कि वह जनता का लोकतंत्र में विश्वास दिलाए और उसके प्रसार का आंदोलन चलाए। विपक्षी शक्तियों का सहकार और एकता इस दिशा में बड़ा कदम होगा। संजय उसमें सहयोग करने को कृत संकल्प है। कृषि और कृषि आधारित उद्योग के क्षेत्र पूरी तौर पर राज्य सरकारों के जिम्मे है। पर जून 2020 में केंद्र सरकार ने एक कृषि अध्यादेश जारी किया जिससे पूरी खेती किसानों बड़ी कंपनियों के हाथ में चली जानी। बड़ी जल्दबाजी में महामारी के दुखद दिनों में सरकार ने तीन कृषि बिल लोकसभा में 18 सितंबर को पास कराए 22 सितंबर को बिना उद्घाटन बहस कराए और अल्पमत में हाते हुए सरकार ने इसे राज्यसभा से भी पास कराने की नौटंकी रखी

ये बिल चार पुंजापनियों की साठ गोंठ से बनाए गए थे। इसका सबूत है कि कानून बनने के कई साल पहले ही अड़ानी न अनाज भंडारण और व्यापार के लिए जरूर कोठार कारखाने बना लिए थे

पर जल्द ही देश भर के किसानों ने एक ऐतिहासिक अहिंसक और क्रान्तिकारी आंदोलन खड़ा किया, जो हमेशा देश के इतिहास में दर्ज रहेगा। किसानों का विरोध, बिल के पास होने के पहले ही अगस्त 2020 से शुरू हो गया था। ये विरोध सप्ताह दर सप्ताह ज्यादा तेज और व्यापक होते गए। प्रदर्शन, बंद रेल शक्ति, रास्ता रुका सब बढ़त हो गए। जल्द ही किसानों का विरोध दिल्ली और उसकी सभी सरहदों पर देश डाला, धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह के रूप में शुरू हुए और लगातार कायम रहे। घरों से दूर खुले मैदानों में और सड़कों के किनारे धूप, गर्मी, ठंड में पूरे साल भर लंबा यह सत्याग्रह किसानों के बैय सहम और संगठन कुशलता को बड़ी मिशाल है। नवंबर 2021 में अब मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की, तब वह उग्र आंदोलन स्थगित किया गया।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को सरकार को बाध्यकारी कर्तव्य बनाने के कानून तथा अन्य किसान हितकारी विषयों के लिए 'संयुक्त किसान मोर्चा' के तहत आज थी यह आंदोलन चल ही रहा है। पर सरकार और उच्चतम न्यायालय दोनों एकतरफा कामटो बना कर टालमटोल कर रहे हैं। जाहिर है कि सरकार

यह कानून नहीं बनाना चाहती है

संजय ने इच्छा और अपने सहमता व सहयोगी संगठनों 'किसान मजदूर परिषद' तथा 'राष्ट्रीय किसान सम्मेलन समिति' द्वारा स्थापनायन कामटो की सिफारिश में न्यूनतम समर्थन मूल्य को गणना और कई अन्य धराओं की जुटियों को वर्षों से उठाया है। संयुक्त किसान मोर्चा में किसान मजदूर परिषद भी शामिल है

उत्तर बंगाल और असम में चाय की खेती और सारे देश में अनाज के साथ ही दलहन, तेलहन, गन्ना, दुध सब्जियाँ, फलों, कपास, मछलियों, अंडा मांस, मसाले सभी को किसानों तथा उनके मजदूर वर्षों से संकट में हैं। संजय उनकी सुरक्षा चाहती है और मांगों का समर्थन करती है। क्षेत्र में अड़ानी के वंदरगाह से मछुआरों और नदीय जनता की मुश्किलों के कारण विरोध चल रहा है। पर भाजपा और सीपी (एम) उस परियोजना का समर्थन कर रहे हैं। वन और पर्यावरण नीतियों में जो बदलाव किए गए हैं वे आदिवासियों के हितों के विरुद्ध हैं। धड़िल्ले से वन क्षेत्रों में खदानों के पड़े किए जा रहे हैं और जंगलों को कटाई हो रही है। खेती क्षेत्र और किसानों मजदूरों के हित के लिए संघर्षरत रहने को संजय प्रतिबद्ध है

देश में शिक्षा की हालत पहले से ही बुरी रही है। कांग्रेस सरकार ने ही 2004 की शिक्षा नीति बना कर सार्वजनिक शिक्षा देने के कर्तव्यों से अपने को मुक्त कर लिया। मोदी सरकार की नीति शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा निजीकरण लाने की रही है। प्राथमिक कक्षा से विश्वविद्यालय तक। सरकारों विश्वाविद्यालयों में तो सौश को बदलने की चरम पर है। वंचित वर्गों और पिछड़े इलाकों के छात्रों के लिए प्रश्रय छात्र छात्रियों और अंतराण वहाँ वह खतम करने जा रहा है। दाखिले के लिए बड़ी राष्ट्रीयी, पोषा विरोधी 'ऑनलाइन' परीक्षाएं लाइ दी गई हैं। इनकी वजह से कंप्यूटर, फोन, इंटरनेट, कागज वगैरह से वंचित पिछड़े और दहली इलाकों के बच्चों के लिए दाखिले के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं

काबिड महामारी के दौर में दो साल स्कूल कालेज बंद रहे। वंचित वर्गों के बच्चे - युवाओं के लिए प्राइवेट कंपनियों और स्कूल-कालेजों की 'ऑनलाइन' पढ़ाई संभव नहीं थी, नार्ताजन वं बुरी तरह पीछे छूट गए। इस नुकसान को पाटने के लिए कुछ नहीं किया गया

दहली घूर दराज क्षेत्रों को विरल आबादी में स्कूलों में कम

कच्चे बता कर उन्हें बंद करने की नीति लाई गई है। अकेले झारखंड में 26 हजार ग्रामीण स्कूल बंद किए गए। अन्य राज्यों में भी स्कूल बंदी की संख्या इसी अनुपात में होगी। इन सबों को तत्काल फिर से खोला जाना चाहिए और शिशुओं की धारणा की जानी चाहिए।

सर्वजनिक विस्तर संश्लेषण दशवासी को स्वास्थ्य सेवा देने में भी सरकार विफल रही है। भाजपा सरकार ने तो इस जिम्मेदारी से हाथ बिलकुल छींच लिए हैं। उन्होंने यह काम निजी अस्पतालों और इश्वरस कंपनियों को सरकारी पैसों देकर, मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार के लक्ष्यों पर केंद्र देश में खड़ा किया है 'आयुष्मान भारत', 'अटल बिलानक' 'प्र.म. आवास' आदि योजनाओं, सोनीएस, इएसआईसी वगैरह में निगमों का कोई सही इंतजाम नहीं है। इस सब में व्यापक भ्रष्टाचार की सूचनाएं मांडिया में निर्यात आती रही हैं।

एनएमिया, मलेरिया, तपेदिक (टीबी), कुपोषण, अंधापन, पानी तथा संग्रहण पर काम पाने के लिए तो जन स्वास्थ्य की कोई सक्षम व्यवस्था अब तक बनी ही नहीं है।

5 अगस्त 2019 का भाजपा की केंद्र सरकार ने संसद में एक प्रस्ताव पास कर धारा 370 से मिली जम्मू कश्मीर - लद्दाख की विशेष स्थिति (स्पेशल स्टेटस) को खत्म कर दिया। यह जम्मू कश्मीर की विधानसभा को मिले विधायक अधिकारों का सार्वभौम उल्लंघन था। वह भाजपा के मुस्लिम विद्वेषी चरित्र और धार्मिक उत्प्रेरणों के कारण चुनावों में लाभ देने की खतरनाक चाल थी। महीने-साल तक कश्मीर में फोन इंटरनेट सेवा, जनता की साधारण आवश्यकताओं को बंद कर, दंगल प्रमुख नेताओं को जेल भेज या नजरबंद कर दमन की क्रूर प्रदर्शनों की गईं। विभिन्न राज्यों - गोवा, पुद्दुचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड, सिक्किम अन्य सभी उत्तर पूर्व के राज्यों में जमीन की मिलिक्वयट और खरीद विक्री पर कश्मीर जैसी ही कानून और प्रतिबंध हैं। पर कौटिल्य विषय में सरकार ने केवल कश्मीर में ही बदले कानून लागू किए। भाजपा समर्थकों ने खुले बयान देकर कश्मीर को खरीदने और वहां की महिलाओं के अपमान का एलान किया। घृणा फैलाने की यह बोधदायक घटना थी। सज्ज ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस बहाल करने की मांग की है और अब भी उस पर काम है।

शासक दल और पूंजीपतियों की सांड-गांड और आपसी लीन-दीन का देश में पुराना सिर्नासला रहा है। सरकार उन संश्लेषणों गुप्त और खुले रूप में बड़े भावों देती रही है। बदले में पूंजीपति उस दल को चुनाव जीतने के लिए बड़ा पैसा दान देते हैं, जो अमूमन चोरी छिपे होता रहा है। जनता को यह मालूम नहीं होता है कि किन-किन के बोध इस बड़े पैसों का लेंच देना हुआ है।

भाजपा सरकार ने चुनावी बॉन्ड में गुप्त दान का प्रत्यक्ष लोकर चुनावी भ्रष्टाचार का कानूनी संरक्षण दे दिया और जनता को बिल्कुल अंधेरे में पहुंचा दिया। अब जनता को कुछ नहीं मालूम होगा कि किस संघ या कंपनी ने किस दल को पैसों दिए। यह चुनावी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। इससे ताकत से भाजपा की जीत पड़ने से आधी तब हो जाती है, पार्टियों के चुनाव खर्च पर सीमा न रखने, किसी भी सीमा तक धन हासिल करने, विदेशों से दलों को मिलने वाले धन की कोई जांच न करने के प्रावधान इस भ्रष्टाचार का कानूनी मान्यता देते हैं। सज्ज इन सभी नियमों की समीक्षा और पारदर्शिता लाने के बदलाव की मांग करती है।

चुनाव के पहले और बाद भी भाजपा अपने अकुल पैसों और ताकत के दल पर विपक्षी विधायकों को सेकड़ों करोड़ों को कोमत पर खरोब कर राज्यों में विपक्षी सरकारों को तड़ानी और अपनी सरकार बनाती है। उत्तर पूर्व के छोटे राज्यों के विधायक फल से हो पुरो तरह केंद्र की सत्ताधारों पादों के साथ हो जाते रहे हैं। अभी वे सभी सरकार भाजपा के कब्जे में आ गई है। एफएएसपीए के द्वारा उत्तर पूर्व राज्यों में जनता का दमन अभी भी बरकरार है।

विभिन्न अनुमानों के मुताबिक अहली की कंपनियों पर विभिन्न बैंकों का कर्ज दो से तीन लाख करोड़ रुपये के बीच है। जनता के पैसों से ही वह रेल स्टेशन, हवाई अड्डे और जनता / सरकार की अन्य संरचनाओं को खरोब कर बुनियाद का दूसरा / तीसरा सबसे धनी आदमी बना है। केंद्र के शासन में बदलाव होने पर ऐसे चार पूंजीपति देश और नगरिकता छोड़ देते हैं। अहली द्वारा कर्ज नहीं लौटाने की हानि में कई सरकारी बैंकों के डूब जाना का खतरा है।

भाजपा सरकार को विदेश नीति भी कुलमुल और अस्पष्ट

रही है। पाकिस्तान के प्रति सरकार के वतांव के कारण केवल अपने देश में धार्मिक नफरत फैलाने की इच्छा रहा है। नगरिक खेलजोल के लिए संभव आपसी यात्रा खेलकूद, फिटनेस, साहित्य, कला संस्कृत धार्मिक पर्यटन वगैरह को भी नामुर्मादन कर दिया गया है। पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ में भी मानवीय सहायता नहीं की गई। अफगानिस्तान यूक्रेन पर रूस का साम्राज्यवादो हमला निहत्थे नागरिकों के घर, अस्पताल स्कूल कॉलेज, बिजली-पानी सप्लाई को बर्बाद करने का युद्ध अफराक, हांगकांग में नागरिक अधिकारों का हनन चीन में उइगर समुदाय का उत्पीड़न, ताईवान पर चीन द्वारा हमले की तैयारी चीन में जो जिनोपंग द्वारा शासन पर मानाशाही कब्जा त्वालीने अमरीका में वायपेंच का उदय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के शोषण प्रवर्तक नियम जैसे सारे महत्वपूर्ण मसलों पर भी सरकार अपना स्पष्ट रुख नहीं बना सकी

चुनाव जीतने और देश की सत्ता संसाधन पर काबिज रहने के लिए भाजपा देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, नफरत का बानाबान, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों पर हिंसक हमले मौस्जिद-मजारों का हाथपादने समान नागरिक कानून लाने की अफवाह फिल्मों साहित्य को नफरती व्याख्या पार्टी स्वयं और विभिन्न नामों से संगठित अपन गुणों द्वारा करती रही है वोट बंटारन के लिए सरकार और भाजपा द्वारा हिंदू जनता के दिल में डर और अमरुक्षा की भावना पैदा की जा रही है। इसमें केंद्र और प्रदेशों को भाजपा सरकारों का संरक्षण और सहयोग उन गिरोहों को मिलता रहा है

मादो सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद ही असम में लागू किए गए 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)' वाली पुर्निसया अपीडक कागवाइ को पूरे देश में लागू करने की मंशा का प्रचार किया 11 दिसंबर 2019 को भाजपा सरकार ने संसद से 'नागरिकता संशोधन बिल (सीएए)' पारित किया जिसमें पड़ोसी देशों से आए मुसलमानों के अलावा अन्य धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया यह 1955 के नागरिकता कानून का पुष्टतापूर्ण संशोधन था सरकार के इस पक्षपातपूर्ण इरावों के विरुद्ध देश भर में विरोध शुरू हुए 15 दिसंबर 20 9 को दिल्ली के शाहीनबाग में मुख्यत मुस्लिम औरतों की

अगुवाई में एक अनवरत प्रभावशाली धरना शुरू हुआ जिसमें सभी समुदाय के यष्टाप्रय लोगों ने शिरकत की। जल्द ही देश में दजनों शहरों में इसी स्वरूप के अनवरत प्रभावशाली धरने शुरू हो गए ये सभी धरन 24 मार्च 2020 को कोविड के संक्रमण से वधन के लिए खतम किए गए

शिक्षा संस्थानों, पुलिस बल, प्रशासन, मीडिया और अवर न्यायपालिका में ध्रुवीकरण का प्रयास दोनों से बित्ता जा रहा है यह जहर देश को टुकड़ों में तोड़ सकता है सशक्त प्रयास के बावजूद इस जहर को सफाई में दशकों का समय लगेगा। भाजपा दल और सरकार की गलत नीतियाँ, खराब शासन और खराब बलव के कारण पिछले चार वर्षों में कई क्षेत्रीय पार्टियां ने शक्ति की पहल की है। सजप इस पहल का समर्थन करती है उम्मीद है कि ये दल आपस में जल्द विस्तृत विमर्श कर सझा नीतियाँ और कार्यक्रमों का खाका जनता के सामने लाएंगे

देश में लोकतांत्रिक समाजवाद लाने के अपने दीर्घकालीन उद्देश्य को जल्द पूरा करने के लिए सजप अन्य एक लक्ष्यीय आंदोलनों समाजिक सहिष्णुिक राजनीतिक मजदूर किसान, धार्मिक सुधारवादो, शिक्षा सुधार अकादमिक शोधरत वगैरह संगठनों से सहकार और संयुक्त कार्यक्रम करता रहा है हमारी यह नीति और प्रयास आगे भी बरकरार रहेंगे। पिछले चार वर्षों में हम संगठन का विस्तार और अमोनी कार्यक्रम ज्यादा नहीं कर पाए हैं अब वह नजो से करने की जरूरत है।

इस प्रस्ताव में सजप के तर्जिए से देश दुनिया के हालातों का सर्वेक्षण किया गया है सजप को मूलभूत और व्यापक विचारधारा पार्टी के दस्तावेजों और विमर्शों कार्यक्रमों में दजे है। उन्हें ज्यादातर साथी जानते ही हैं। एक सवाल होता है कि सजप के आगे की राजनीतिक दिशा आर्थिक विकास के लिए नीतियों का खाका और विस्तृत कार्यक्रम क्या होंगे प्रस्ताव के ये पहलू इस सम्मेलन में विमर्श और अगली राष्ट्रीय कावकरिणों के विमर्शों से तैयार होंगे। आने वाले राज्या के और 2024 के लोकसभा चुनावों में लोकतंत्र और लोकहित समर्थक सरकारें बनाना देश की जनता के लिए बड़ी चुनौती है इसके लिए सजप अपनी पूरी ताकत लगा कर काम करेगी।

(सगले अंक में सामाजिक प्रस्ताव)

आदिवासी, देशज, बाहर के कौन

किशन पटनायक

(उत्तर बंगाल के जाल्पाइगढ़ जिले के तहत जटेश्वर में 6 दिसंबर को समता कब्र के स्थापना दिवस के मौके पर समारोह आयोजित किया गया। इसमें मौजूद लोगों के बीच किशन पटनायक के इस लेख की प्रतियां वितरित की गईं। इस लेख का बंगला अनुवाद भी विकसित किया गया। किशन जी का यह लेख सामाजिक जाति के दिसंबर 2002 के अंक में छपा था, जिस संभावनाओं को तलाश नामक किताब में भी इसे शामिल किया गया। समारोह में उत्तर बंग केंद्र शामिलों संयोजक, पृथक राज्य टाकीर प्रार्थनाकला पर चर्चा हुई। गौरवजन्य है कि इन दिनों उत्तर बंगाल के भाजपा के एक मौसद उत्तर बंगाल राज्य की प्रांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के करिष्ठ नेता इस प्रांग की भाजपा की प्रांग मानने से इंकार कर रहे हैं वास्तव में अंग्र लीगा के बीच ऐसा कोई गग हो नहीं उठ रहा है। भाजपा के नेता बांड को राजनीति के तहत सुनियोजित ढंग के एक धर्म की स्थिति पैदा करने में जुटे हैं। इसी के महानजर उनकी घान खानने के लिए इस विषय पर चर्चा की गई। इस दिशा में किशन पटनायक का लेख भी स्पष्ट रूप बताने में मददगार है इसलिए इस लेख को यहाँ रखा जा रहा है।

अंग्रेजी में इंडीजनस का शब्द का अर्थ देशीय देशज होता है। इसी अर्थ में इस शब्द का इस्तेमाल हम करते आए हैं इसका अर्थ आदिवासी या आदिम आदिवासी से अधिक व्यापक होता है। लेकिन यूरोप का अनुभव सबके ऊपर थोपा जा रहा है यूरोप का यानी गोरी जाति का अनुभव

एक खास प्रकार का है उनके लोग अमेरिका ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में जाकर बस गए और बड़े भूखंडों में उनकी का वर्चस्व हो गया। मुख्य लोग वे हैं जबकि पुराने लोग देशज (इंडीजनस) के रूप में चिह्नित हो रहे हैं देशज लोग बिल्कुल हाशिए में घले गए हैं मानो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया उनका देश नहीं था।

इस अनुभव के दांचे को भारत पर लागू करना गलत परिणामों को जन्म दे सकता है आर्य बाहर से आए या नहीं इस तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। इस प्रश्न की एक कड़ी बन सकती है - मुसलिमान बाहर से आए या नहीं इसी बाहर से आए या नहीं आदि इन प्रश्नों के वैचारिक बिंदु बना कर



नकारात्मक भावनाओं को तब कंधा जा सकता है।

प्राचीन काल में राष्ट्रों के (अपेक्षाकृत स्थिर भौगोलिक सीमाओं का लेकर) बनने के पहले जनसमूहों का आवागमन विश्व के अधिकांश भूभागों में होता रहा है और उनके संघर्ष तथा सम्बन्ध होते रहे

पहले संघर्ष, बाद में सम्बन्ध अगर आर्य कहीं से आए तो उसी काल में आए और देशीय हो गए इसलिए यह सवाल उठाना उपयुक्त नहीं है कि आर्य बाहर से आए थे या नहीं यह सवाल भी बंभानो है कि आज 'आर्य कौन है और अनार्य' कौन है?

असली समस्या यह है कि भारत में जो कई प्रकार के जनसमूह आए हैं और सबके सब देशीय हैं, उनमें किस प्रकार के अन्तर्गत हैं और उनमें सम्बन्ध घटित हो रहा है या नहीं? रामायण-महाभारत से काफी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। 'आर्य कहलाने वालों ने एक अर्धनप्रथा विकसित कर ली रामायण-महाभारत काल के इन आर्यों से कुछ लोग

देश के बहुत बड़े भूखंड में थे, वे स्वतंत्र थे, कहीं-कहीं अधिक वैभवशाली और पराक्रमी थे। धीरे-धीरे ब्राह्मण-क्षत्रिय यानी जातिप्रथा वाले लोगों का बचस्व बढ़ता गया और दूसरी क्षी संस्कृति गौण होने लगी। दोनों प्रकार के लोगों का मिश्रण दिखाई पड़ता है। महाभारत में बहुत ज्यादा समन्वय का यह धारा बौद्ध काल तक, छठी शताब्दी तक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। उसके बाद जातिप्रथा के नियम कट्टर होने लगे। उसका एक सुदृढ़ व्यवस्था बन गई, जिसकी शुरुआत शूंग वंश या गुप्त काल में मानी जा सकती है। प्रारंभिक काल में जातिप्रथा ने शायद समन्वय का सपना बनाया होगा। किसी का द्विज और किसी को शूद्र का स्थान देकर अपना लिया होगा।

लांकन परिपक्व हान के साथ-साथ जातिप्रथा ने सिर्फ एक विषमता का ढांचा बना बल्कि अत्याचार और आर्थिक शोषण की एक व्यवस्था बन गई। इसे बहुत सारे जनसमूह थे जिन्होंने जातिप्रथा के ढांचे को कभी स्वीकार नहीं किया। उनमें वे प्रमुख हैं जिनको हम आदिवासी कहते हैं।

अगर हम ब्रिटिश काल से पहले के भारत के सामाजिक भूगोल को आंखों के सामने रखते हैं तो पाएंगे कि भारत के ज्यादातर (राज्यस्तरीय, जिलास्तरीय) इलाकों में ब्राह्मण-क्षत्रिय का बचस्व नहीं था या फिर जातिप्रथा ही नहीं थी उससे से ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र इसी प्रकार का था। ब्रिटिश शासन तथा आधुनिक सभ्यता ने देश के कान-काने में शासन व्यवस्था की इकाई बना कर द्विज जातियों को स्थापित किया। ब्रिटिश काल में जाति का ढांचा भारत में सर्वत्र प्रतिष्ठित हो गया। असमियों को उसमें जोड़ लिया गया लांकन 'आदिवासी' समूह उसके बाहर अभी तक है। इसको कौमन थे चुका रहे हैं।

जातिप्रथा और आधुनिक सभ्यता ने मिल कर आदिवासियों को ऐसा कर दिया माना यह देश उनकी नहीं, यानी उनका लिए नहीं है। जातिप्रथा ने उनका समाज से अलग-थलग माना लेकिन आधुनिकीकरण ने उनको आर्थिक व्यवस्था से, जीविका से, आवास स्थलों से विस्थापित कर दिया। भारतीय समाज में दलित सर्वाधिक घृणित है तो आदिवासी सर्वाधिक बहिष्कृत, दबाया हुआ, वंचित और निरक्षर है। आजाद भारत में अभी तक यह सिलसिला चल रहा है। आधुनिक विकास

और उसके अहंतागोकरण का सिलसिला रहेगा तो आदिवासियों की नियति बदलनवाली नहीं है। उनकी भाषा, उनकी कला, उनका हुनर लगभग समाप्त हो गया है।

इस समस्या का समाधान 'कौन बाहर से आया' वाले सूत्र से नहीं होनेवाला है। न अधिकारी का लंबा फेहरिस्त बना कर इसका समाधान ढूंढा जा सकता है। सामाजिक कट्टीकरण यानी जातिप्रथा उसका प्रारंभिक दुश्मन थी। इस वक्त ग्लोबलीकरण और आधुनिकीकरण इसके सबसे बड़े शत्रु हैं। पूरी दुनिया में ग्लोबलीकरण को जो व्यवस्था चलाई जा रही है उसके सोपानकृत (स्वयंराकोकल) ढांचे में किसी भी सबसे ऊपर गोरी चमड़ीवाले नराल है। इस नस्लवाद के द्वारा परिचालित विक्रम के ढांचे में किसी भी प्रकार की 'अधिकारी' की सूर्या में आदिवासियों को नियति सुधरनेवाली नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में एक परिपाटी बन गई है कि दुर्बल समूहों के लिए कुछ अधिकारों का निर्दिष्टन कर दिया जाए और अधिकार का एक घोषणापत्र जारी कर दिया जाए। विषयना के बुनियादी ढांचे को बदले वीर अधिकारों पर अमल नहीं हो सकता। गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाला भारतीय संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। पूंजीवादी ग्लोबलीकरण में सबके लिए एक सोपान निर्धारित है। कौन कितना नीचे रहेगा, इसका फैसला हो चुका है। अधिकार का कोई काम वहां नहीं है।

आदिवासी को अधिक स्वायत्तता चाहिए और विकास का एक ऐसा अधिक ढांचा चाहिए जिसका लक्ष्य समानता और स्वावलंबन हो। जंगल ठसका होना चाहिए, जल और जमीन पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। आदिवासी बहुत इलाके को अलग राज्य बना देने से भी आदिवासी को शोषण बंद नहीं हो जाता है। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी है। एक नदी कंपनी का छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक नदी बेच दी है। उस नदी पर आदिवासियों तथा अन्य जनसमूहों का अधिकार समाप्त कर दिया गया जो हजारों साल से था। हमलोग केवल अधिकार की बात न करें, अधिकार के साथ साथ समतावादी ढांचा और नई विकास नीति चाहिए, जिसमें जनभगीदारी हो। और भागीदारी का मतलब 'दायित्व' होता है। ट्रेड यूनियनों ने 'अधिकारों' की एक गलत संस्कृति चलाई थी।

गांधी पर प्रहार

अत्युत्तानंद किशोर 'नवीन'

एक माह पहले एक पारिवारिक कार्यक्रम में राजनैतिक हत्याओं पर बातचीत चल रही थी। जब गांधी हत्या का प्रसंग आया तो एक समादृत रामदेववादी ने आश्चर्य भाव से टिप्पणी की 'गांधी की हत्या देश के लिए की गई थी।' यह सुनते ही मुझे कांठ मार गया, और दूसरे भी झटप्रपन्न रह गए।

अध्यात्म और योग के जा प्रशिक्षण शिविर चलते हैं उनमें सायास तरीके से राजनीतिक व आर्थिक हित समाहित किए जाते हैं। रामदेव महाराज के शिष्य में दर्जना वैतर लग रहते हैं उनमें महापुरुषों की तस्वीरों के मध्य महात्मा गांधी को भी जगह दी जाती है। रामदेववादियों का मानस घटल पर यह धारणा कैसे बढमुस हो गई कि गांधी की हत्या बश के लिए की गई थी। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उच्च स्तरीय हलकों में इस तरह के मानस निर्माण की कार्यशालाएं चलाइ जाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति (जहाँ भी योगाचार्य) कभी किसी दल विशेष का प्रवक्ता नहीं बन सकता। रामदेव महाराज ने 2014 के चुनाव पूर्व भाषणों में जनता से वादा किया था कि भाजपा के सत्तासीन होने पर पेट्रोल 35 रुपये लीटर घिकगा और विदेशी बैंक में जमा कालाधन भारत में आ जाएगा। आज जब केंद्र योगयुक्त से इसकी यथा करता है तो वह तिरस्किता उठते हैं 'दरअसल संत को सीकरी (फतेहपुर सीकरी, जो अकबर की राजधानी थी) से क्या काम? जब शहशाह अकबर ने संत कुंभनदास को मिलने के लिए बुलाया तो कुंभनदास ने अकबर से कहा था 'संतन को सीकरी से कोन काम / आवत जात पराहिणं दुट्टा, बिसरो गया हरनाम। जिनको मुख देख कुछ उपजत, तिनको करनी परियो परनाम। कुंभनदास लाल शिरधर बिन और सने बे काम।'।

गान्धामौ बल्लभभाचार्य के शिष्य कुंभनदास परम दरिद्री

रहने पर भी कभी किमी राजा महाराज से धन लेना स्वीकर नहीं किया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने प्रान्त स्मरणाय लांगो में गांधी को भी स्वीकार किया है। मगर किसी भी संघी को थोड़ा भी कुरांदिए तो गांधी बिषयक जुगुप्सा फौरन झलक जाएगा। गांधी की गौडसे द्वारा की गई हत्या को वह दुरस्त ठहराएगा।

भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में दिल्ली में हुई थी। इस सम्मेलन में गांधीवादी समाजवाद को स्वीकार किया गया था। मगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक का न तो गांधी से और ना ही समाजवाद से कोई सरोकार है। इसके उलट गौडसे पूजक व गांधी निंदक को पार्टी में तबज्जो पारितोषिक व प्रोत्थति दी जा रही है।

गांधी विरोध के घुर दक्षिणपंथी से लेकर घुर वामपंथी, अवेंढकरवादियों के एक बड़ा समूह व धार्मिक संगठनों में अद्भुत साम्य है। गायत्री परिवार के प्रवक्त श्रीराम शर्मा आचार्य ने भले ही आजादी की लड़ाई में कारावास की यातना झली हो, मगर उनके अनुयायी गांधी निंदा में पोछे नहीं है। आर्य समाज ने पंजाब में हिंदू सिख के दरार को और भी चौड़ा करने का काम किया है। आर्य समाजियों ने हिंदुओं को मदुमशुमारों में पंजाबी की जगह हिंदी मातृभाषा गलखने को प्रोत्थन किया, नर्वाक व पंजाबी का ही ओढ़ने बिछात है। चार दशक पूर्व तक सिवान था कि हिंदू अपने एक संतान को गुरु की सेवा के लिए सिखों बनाता था। रांटी चटो का संबंध तो अब बीते युग की बात हो गई है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी के एक कार्यकर्ता (इन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ) तो इतने उत्तेजित हो प्रलाप करने लगे, 'गांधी को गोलरी मार देना एकदम ठीक था।' यह सुनते ही मुझे अलौगढ़ की तशकथित



साध्वी पुला शकुन पांडेय का स्मरण हो आया जिन्होंने 30 जनवरी 2019 का एयरगन से गांधी की तस्वीर पर गोली चलाई थी। कबोरपैथी भी अपने धार्मिक प्रवचनों के मध्य भाजपा को मत देने का आह्वान करने हैं। अभिप्राय यह कि हिंदू धर्म को लगभग सारी साखाएँ प्रशाखाएँ गांधी विरोधी भाजपा को जिताने के लिए अपने अनुधर्मियों को लायबंद करती है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अभी खुल कर गांधी विरोध (कुछ सांवेधानिक मजबूरियाँ भी हैं) नहीं कर पा रहा है। नेहरू विरोध का अघ्याय खत्म होते ही गांधी विरोध प्रारंभ हो जाएगा। एक बानगी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का लैं अमृता कहती हैं, 'महात्मा गांधी पुराने भारत के राष्ट्रापिता हैं जबकि नरेंद्र मादी नए भारत के राष्ट्रापिता'। वैसे गांधी की चरित्र हत्या का सुनियोजित प्रयास वर्षों से बटस्तूर चला आ रहा है।

कम्युनिस्टों का भी गांधी विरोध पुराना है। उनका स्पष्ट मानना है कि गांधी पूंजीपतियों के हितेशी हैं। औद्योगिकीकरण के विरोधी हैं, गांधी का ट्रस्टीशिप एक धोखा है, वे समाजवादी क्रांति के राह में बाधक हैं। कम्युनिस्टों ने यह दुर्भावना जन जन तक फैलाई कि गांधी चाहत तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुक सकती थी। गांधी इर्विन समझौते में भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी के बचाने की मांग शर्त रूप में शामिल नहीं थी (यह शर्त में शामिल हा भी नहीं सकता था)। मगर गांधी ने इस मांग को उपसंहार में रखा था। गांधी जी ने इर्विन को लिखा, जनमत का सम्मान करते हुए फांसी नहीं दी जानी चाहिए।' अपने तई गांधी ने पूरा प्रयास किया कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी न दी

जाए। वास्तविकता तो यह है कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी जयगोपाल, फणान्द्रनाथ घाष व हंसराज वोहरा के मुखबिर बन जाने के कारण हुई थी। उसके उलट बहुतरे कांग्रेसी नेताओं ने प्रच्छन्न तरीके से क्रांतिकारियों को मदद ही की थी। जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार के हाजीपुर के गांधी आश्रम' में भगत सिंह दो रात उठरे थे। चंद्रशेखर आजाद की अंत्येष्टि (जो बहुत सख्त पहर में हुई थी) में पींडित नेहरू को पत्नी कमला नेहरू व आजाद के दूरस्थ के रिश्तदार बिनायक मिश्र शामिल हुए थे। आपनो शाहादत से पूर्व आजाद नेहरू जी से मिले थे और नेहरू ने उन्हें 1400 रुपये की आर्थिक मदद की थी। यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में नेहरू पर यह आरोप लगाया था कि भगत सिंह जब जेल में थे तो वह कभी उनसे मिलने नहीं गए। वास्तविकता तो यह है कि नेहरू भगत सिंह से जेल में गए थे और इस खबर को टिक्कून छापा था। कोई पलट कर उनसे यह पूछें कि क्या केशव बलिराम हेडगेवार, गुरुजी गालवरकर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल में भगत सिंह से मिलने गए थे? भगत सिंह के बकील प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता आसफ अली थे। काकारी केस के क्रांतिवीर रामकृष्ण खत्री के सुपुत्र उदय खत्री जो ने मुझे बताया था कि जेल से रिहा होने के बाद नेहरू जी ने खत्री को माटरगडो से पूरा इलाहाबाद घुमाया था। दो साल पहले लाखज जागरण संस्करण में यह खबर छापी कि केशव हेडगेवार ही कोकली केस का केशव चक्रवर्ती थे। लेकिन तुरंत इस मिय्या खबर की पॉल खुल गई।

भल अंबेडकरवादियों की बात। दलितों का एक बड़ा तबका गांधी अंबेडकर पूना पैक्ट का लेकर गांधी का कटु आलोचक है। मेरे सामने एक दलित ने गांधी के ऊपर जो खिनीनी टिप्पणी की उसे लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। दलितों की दृष्टि में गांधी दलित विरोधी थे।

दरहकीकत गांधी से बड़ा दलितों का हितेशी तो मुझे कोई और नजर नहीं आता। गांधी का ही यह सपना था कि वह भंगी बस्तो में रहते थे और सफाई के काम को प्राथमिकता देते थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के यहाँ एक दलित आकर

उहरा था। उसने शौचालय का इस्तेमाल किया। शौचालय ऐसा था कि हर बार उसे साफ करना पड़ता था। कस्तूरबा ने साफ नहीं किया तो गांधी ने गुस्से में उसे घसीट कर बाहर निकाल दिया था। एक दलित परिवार को गांधी ने आश्रम में रखा तो लगभग सारे आश्रमवासी विरोध में सामने आ गए। दानदाताओं ने आर्थिक सहयोग रोक दिया। गांधी अपनी मान्यता पर अटल रहे। डा. सुशीला नैयर (जो उस जमाने में एम्बोयीएस डाक्टर व गांधी जी के सचिव प्यारेलाल की बहन, आजाद भारत में स्वास्थ्य मंत्री बनीं) ने लिखा है, 'एक दलित कार्यकर्ता को दस्त होने लगा तो गांधी ने उसके मल का परीक्षण करना शुरू किया कि दस्त आखिर क्या खाने से हुआ है।' उनके रचनात्मक कार्य का एक मुख्य अंग था अचूतताथान। उनके अखबार का नाम ही था हरिजन। बाद के दिनों में गांधी उसी विवाह को आशीर्वाद देते थे जिसमें एक पक्ष निश्चित रूप से दलित हो। दलितों के मंदिर प्रवेश कराने में गांधी के ऊपर हमलें भी हुए। मैं एक ऐसे दलित अधिकारी को जानता हूँ जिन्होंने अपने स्वजातियों के मध्य घर बनाया। बाद में उन्हें अपने ही स्वजातियों से घिन आने लगा, बाद में घर बेच कर बाहर निकल गए।

मुस्लिम लोग का नेतृत्व गांधी को महज एक हिंदू नेता मानता था। जिन्ना की चिड़ कोई छिपी हुई नहीं थी। डायरेक्ट एक्शन वाले मुस्लिम लोग को कार्रवाई से कोलकाता में मुसलमानों को अपेक्षाकृत न्याया जायमाल की क्षति हुई। तब बंगाल के प्रधानमंत्री (उस वक्त मुख्यमंत्री का पद नहीं था) सुहरावर्दी गांधी के साथ हो 'हैंदरो मेंसन' में रहने लगे। बहो गांधी जब नौआखाली जाते हैं तो सुहरावर्दी असहयोगी हो जाते हैं। गांधी को गालियाँ दी जाती हैं, उनके रास्ते में पैखाना डाल दिया जाता है, जिस गांधी स्वयं साफ करते थे। नंदवारे के बाद चौधरी खल्लिकुम्मा भारत में ही रह जाते हैं, जो मुस्लिम लोग के चोटी के नेता थे। गांधी जी ने खल्लिकुम्मा को करांची विभाजन से भेजा कि वह जिन्ना से मिल कर हिंदुओं का पलायन रोकें ताकि गांधी का काम दिल्ली में आसम हो सके। मगर खल्लिकुम्मा करांची ही रह गए। गांधी का अपना तीसरा बेटा रामदास उन्हें (गांधी का) हिंदूदोही मानता है। रामदास का वह पत्र गांधी खल्लिकुम्मा को दिखाते हुए

बेदना प्रकट करते हैं। खल्लिकुम्मा ने अपनी कित्ताब पाक्षवे टू पाकिस्तान में इसका विस्तार से जिक्र किया है।

अतिपतः गांधी के अपनों ने भी उन्हें छोड़ दिया। विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस कार्यसमिति ने बिना गांधी की जानकारी के ही स्वीकार कर लिया था। आजाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इसके लिए उन्होंने नेहरू से पत्राचार किया था। नेहरू बाद में पलायन कर गए। देश स्वतंत्र होते ही गांधी के सपनों का भारत बिखरने लगा। गांधी ने कहा था कि बायसराय (राष्ट्रपति) भवन को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए। मंत्रोगण छोटें घरों में रहे।

आज का नौजवान अधनंगे गांधी को हितकरत के भाव से देखता है। मगर इसी अधनंगे फकीर के बारे में वैज्ञानिक आइंस्टीन के कथन को दोहराने का लोभ संवरण नहीं किया जा सकता, 'भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाइ-मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था।'

जब गांधी माउंटबेटन से मिलने गए तो उस वक्त माउंटबेटन की पत्नी ओर बेटे भी साथ थी। माउंटबेटन ने गांधी की पोती मनु से कहा, 'मेरी बेटी तुमसे ईर्ष्या करती है, जब वह तुम्हें गांधी की सेवा करते देखती है।'

रानी एलिजाबेथ (द्वितीय) की शादी में गांधी ने अपने हाथ से बना मेजपोश भेजा था। हीरा-जवाहरातों के मध्य गांधी के उपहार को वह अमूल्य मानती थीं।

आखिर कुछ तो विशेष था ही कि अधनंगे गांधी के आश्रम में देश-दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, राजनेता व राजा-महाराजा सिर नवाते आते थे। माउंटबेटन ने चुं ही नहीं उन्हें 'वन मेन आर्मी' कहा था।

गांधी के न चाहते भी भारत विभाजन व भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी हुई। राम और कृष्ण को तो अवतारी पुरुष माना गया है। तब भी राम-रावण युद्ध हो ही गया। उनके यश में युद्ध को टालना नहीं था। गांधी ने भी अपने तैं विभाजन टालने का पूरा प्रयास किया था। गांधी तो खैर, अधनंगा फकीर था। जो मुल्क अपने नायकों का सम्मान नहीं करता, उसे गिरने से कोई रोक नहीं सकता।

वरिष्ठ समाजवादी नेता अकरम हुसैन नहीं रहे



अकरम हुसैन
(1947-2022)

समाजवादी जन परिषद के वरिष्ठ नेता और पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अकरम हुसैन अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका 20 दिसंबर 2022 को सुबह निधन हो गया। वे 75 साल के थे।

अकरम हुसैन पिछले कुछ महीने से अस्वस्थ थे। अस्पताल से घर आ गए थे। घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। एकएक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें जलपाईगुड़ी के

स्थानीय एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन वही उन्होंने अंतिम सांस ली।

अकरम हुसैन उत्तर बंगाल में समाजवादी नेताओं-कार्यकर्ताओं, खासकर मुस्लिम समुदाय के युवजनों में 'अकरम दा' नाम से पुकारे जाते थे। उनका जन्म जलपाईगुड़ी शहर के एक प्राचीन संपन्न परिवार में 10 जून 1947 को हुआ था। उन्होंने अपने शहर में ही फर्ग्युसन विश्वविद्यालय से उच्च माध्यमिक तक पढ़ाई की। उसके बाद आनंदचंद्र कालेज से राजनीति शास्त्र विषय में ऑनर्स से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। उत्तर बंग विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी कर जलपाईगुड़ी जिला अदालत में बकालती की। बाद में वे कोलकाता और दूसरे जिलों के अदालतों में बकालती करने जाया करते थे। गरीबों, खासकर अल्पसंख्यकों के अदालती मामलों को निपटाने में वे आगे रहते थे। उन्होंने बकालती शुरू करने के पहले कुर्चाबख्श कालेज में अध्यापकी की।

वे कालेज में पढ़ाई करते वक्त ही राजनीति से जुड़े और छात्र राजनीति करते हुए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए। वे जब कालेज में थे, तभी समाजवादी चिंतक डा. राममनोहर लोहिया के सिद्धांतों व नीतियों से प्रभावित हो गए थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। बाद में सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संघर्षित पश्चिम बंग घाय श्रमिक धूनियन से जुड़ गए और घाय श्रमिकों के आंदोलनों में अहम भूमिका निभाते रहे। बाद में वे उत्तर बंगाल में दलितों और आदिवासियों के आंदोलन के अगुआ नेता जुगल किशोर रायबोर और कमल बनर्जी के काफी करीब हुए। वे समाजवादी जन परिषद से जुड़े और इस पार्टी को ताकतवर बनाने में कभी थोड़े नहीं



जलपाईगुड़ी में शोकसभा

रहे। वे राजनीतिक आंदोलनों में ही नहीं, विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में भी बहु-चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उन्होंने जलपाईगुड़ी वेलफेयर आर्गनाइजेशन के उपाध्यक्ष के पद पर रह कर तरह-तरह के समाज-सेवा के कार्य किए।

उन्होंने उत्तर बंगाल के पिछड़े मुस्लिम समुदायों के आंदोलनों में चढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। पिछड़े मुस्लिम समुदायों को ओबीसी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन के लिए अलग-अलग मुस्लिम संग्राम समिति के गठन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। सेन आयोग के सामने मौजूद होने वाली कमिटी में वे थे और उन्होंने आयोग के सम्मने तथ्यों को प्रस्तुत कर पिछड़े मुस्लिम समुदायों को ओबीसी की सूची में शामिल कराने की मांग को पूरा कराया।

वे छात्रावस्था से ही 'आजाद हिंद पुस्तकालय' से जुड़े थे और अरसे तक पुस्तकालय की संचालन कमिटी के सदस्य थे। वे दलित और आदिवासीयों के अधिकारों और विभिन्न मांगों को लेकर 'उत्तर बंग तपसिली जाति ओ आदिवासी संगठन' के सहयोगी थे। संगठन के तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने में कभी भी पीछे नहीं रहे। वे अहिंसा, स्वातंत्र्य, समता

और वैकल्पिक विचारों को लेकर चलने वाले 'समता केंद्र' के सदस्य थे। वे समतामूलक व्यवस्था में विश्वास करते थे। वे जाति व धर्म के नाम पर सत्ता व पीड़ित लोगों के प्रति केवल सहानुभूति ही नहीं रखते, बल्कि उनकी मदद के लिए खड़े रहते थे। जीवन के आखिर समय तक वे सत्य और निष्ठा के साथ समाजवादी राजनीति, श्रमिक आंदोलन, समाज सेवा और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे।

उत्तर बंग तपसिली जाति ओ आदिवासी संगठन (उत्पास), समता केंद्र, समाजवादी जन परिषद, पश्चिम बंग चाय श्रमिक यूनियन की ओर से जलपाईगुड़ी के नेताजी सुभाष फाईंडेशन के हॉल में अकरम हुसैन के प्रति शोक और श्रद्धांजलि व्यक्त करने का घात स्मरण सभा आयोजित की गई। अखिल बंधु सरकार ने उसकी अध्यक्षता की। मिहिर सेन, कमल बनर्जी, शबनम, रंजीत कुमार राय, तुलसी घर, निर्मल घोष दस्तीकार, नरेन दास, पूर्व विधायक गोविंद राय, अमल राय, अबुल हुसैन, मनोतोष प्रमाणिक, प्रदीप बोस, मोमेनूर रहमान ने अकरम हुसैन के बारे में विस्तार से जिक्र किया और श्रद्धांजलि दी।

श्रद्धांजलि

अख्तर हुसैन नहीं रहे

बिहार आंदोलन के दौरान 1974 में पटना के गांधी मैदान में जनसभा होने वाली थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ने इस जनसभा को किसी भी सूत्र में नहीं होने देने का ठान लिया था। पूरे शहर में 144 धारा लागू कर दी गई थी। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसके बावजूद एक

नाट क्व का युवक पुलिसिथा घरे के बीच से दौड़ गांधी मैदान के बीचोबीच बने मंच पर पहुँचा गया और भाइयों से ऐलान करने लगा - भाइयों बहनों... पुलिस के जवान हतभ्रम और बौखलाए मंच को ओर दीड़े और उन्होंने उस युवक को दबाव लिया। वहाँ के जिन्याधिकारी विजय शंकर दुबे के गुस्से की सीमा नहीं रही। वे खुद उस युवक की पिटाई करने लगे और बोलने लगे - तू चपरासी का बेटा होकर नेता

बनने चला है... उन्होंने युवक को पीट कर कुशी तरह से घायल कर दिया और जेल भेज दिया। सरकार के जुल्म को देख कर जन कवि नागार्जुन ने बह रचा - 'अख्तर हुसैन बंद है पटना की जेल में, अख्तर गफूर है मस्त सत्ता के खेल में।' गफूर मुखमंत्री थे।

गांधी मैदान में झंडा फहराने वाला युवक था **अख्तर हुसैन**। समाजवादी अख्तर हुसैन का 11 जनवरी को रांची के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 67 साल के थे। वे आरसे से अस्वस्थ थे। उनकी पत्नी सबीना राज और दो बेटियाँ हैं।

अख्तर हुसैन के पिता हाफिज हुसैन पटना कालेजियट स्कूल के कर्मचारी थे। वे रसायन प्रयोगशाला में कार्यरत थे। उनकी पाँच संतानें थीं। संतानों में अख्तर हुसैन बड़े बेटे थे। हाफिज चाचा पर अपने बौबी-बच्चों के साथ परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। स्कूल से मिलने वाली तनख्वाह से गृहस्थी का चलना मुश्किल था। वे शाम को बीड़ी बनाने का काम करते थे। अख्तर हुसैन की ठीक से पढ़ाई-लिखाई नहीं हो पाई।

रामनाथ ठाकुर ने अख्तर हुसैन को अपने पिता बड़े समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर से मिलवाया। अख्तर हुसैन समाजवादी रचनात्मक गतिविधियों में शामिल हो गए। उनकी 1971 में समाजवादी नेता च पितक किशन पटनायक से मुलाकात हुई। वे किशन जी के संगठन लोहिया विचार मंच में शामिल हो गए। लोहिया विचार मंच

के सदस्य के रूप में उन्होंने बिहार आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। किशन पटनायक के साथ रहने की वजह से वे 1977 में जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए। काफ़ी पहले उनको कर्पूरी ठाकुर से भी दूरी बन गई थी। लोहिया विचार मंच के बाद जब किशन पटनायक की अगुवाई में समता संगठन का गठन हुआ तो वे उसमें शामिल हो गए। शुरू में वे सामयिक वार्ता के प्रकाशक भी रहे। लेकिन समता संगठन में कुछ समय रहने के बाद वे

गैर सरकारी संगठनों से जुड़ गए और किशन पटनायक से अलग हो गए।

1990 में बिहार में लालू प्रसाद की जनता दल को सरकार बननी तो लालू प्रसाद ने उन्हें 15 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष बनाया। बिहार आंदोलन से लालू प्रसाद उभरे थे और अख्तर हुसैन भी। लालू प्रसाद ने उन्हें अपने करीब किया। लेकिन अपने स्वभाव की वजह से उनकी लालू प्रसाद से दूरी बढ़ गई। ताकतवर नेता के सामने बिना लागलपेट थड़ल्ले से अपनी बात कह देना उनका स्वभाव था। एक बार विधानसभा चुनाव में वे उम्मीदवार होते-होते रह गए। किसी पूँजीपति को टिकट मिल गया। वे कलकत्ता (अब कोलकाता) के हाथ रिकशा को हटाए जाने के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए थे।

मालो हालत में रांची की सबीना राज का उनका साथ मिला। उन्होंने उन्हें अपना बना लिया और आखिर तक उनकी देखभाल की। अख्तर हुसैन पटना से आकर रांची ही रहने लगे और आखिरी सांस रांची में ही ली।